₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जनवरी 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

आयोग का हठ छात्रों की जिद्द

पुलिस तंत्र पर नहीं है सरकार का नियंत्रण!

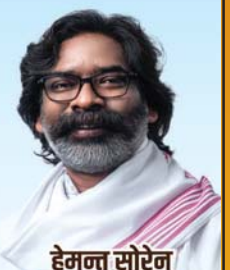

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
गणतंत्र दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
और जोहार
संतोष कुमार गंगवार
राज्यपाल, झारखण्ड
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है। भारत का लोकतंत्र भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है।
आइए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर देश एवं लोकतंत्र की प्रगति में योगदान दें।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

जन-जन की आवाज है केवल सच
केवल सच
Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ
Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो
केवल सच TIMES
आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें
आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा
BHIM UPI
G Pay Paytm
www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in
-: सम्पर्क करें :-
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

Ashirwad
आशीर्वाद
स्व-तंत्र अलौकिक चिकित्सालय
Badauan, Gaya (Bihar)
डायबिटीज, गठिया, चर्मरोग, पथरी,
एक्जिमा, गैस्ट्रिक, माइग्रेन,
बांझपन, ल्यूकोरीया, थायराइड,
मोटापा, श्वास, बवासीर, इत्यादि
जटिल रोगों का उपचार
करा कर थक चुके हैं, तो
सम्पर्क कर सकते हैं :-
Dr. Mantu Mishra
फोन नंबर :- 9939978397
समय :- सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894

नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951

विद्या बालन
01 जनवरी 1978

ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955

दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986

विपाशा वसु
07 जनवरी 1979

ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966

फराह खान
09 जनवरी 1965

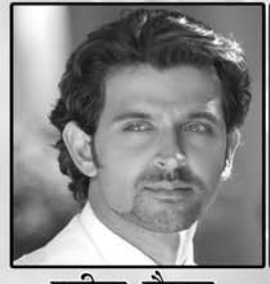

हृतीक रौशन
10 जनवरी 1974

राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973

स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863

प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972

राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963

मायावती
15 जनवरी 1956

जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945

सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897

बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926

बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967

लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865

प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

भगवान भरोसे है हिन्दुस्तान

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

21 वीं सदी के संचारक्रांति के युग में रहने के बाद भी हिन्दुस्तान की आवाम को किसी बात पर तब तक भरोसा नहीं होता जबतक विपक्ष या विदेशी चैनल उसकी पुष्टि न कर दे। लोकतंत्र के चारो स्तंभ भी हासिए पर खड़े हैं क्योकि सभी स्तंभों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से इनपर भी भरोसा नहीं के बराबर है। विलंब से मिलने वाले न्याय की वजह से इंकाउंटर और बुलडोजर का राजनीति करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर मस्जिद खोदने पर पुरातत्व विभाग को मंदिर का अवशेष मिलने लगे है। एक तरफ जय श्रीराम तो दूसरी तरफ माय समीकरण और तो और कोई 15 मिनट में कुरूक्षेत्र का मैदान बनाने पर उतारू है। देश के भीतर जन-बुनियादी समस्याओं के समाधान के बजाय हिन्दू-मुस्लिम और इसाई की कट्टवाद खेल को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ गंगा निर्मल हो रही है तो दूसरी थूक का बाजार गर्म है। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तेवर ने और धार्मिक गुरू एवं कथावाचकों ने हिन्दुस्तान को हिन्दूराष्ट्र बनाने की मुहिम को गति दी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हिन्दुस्तान की कन्फ्यूज वोटरों ने ऐसा जनमत दिया कि मोदी की नींद हराम हो गयी और अयोध्या जैसी नगरी से भी हिन्दुत्व की छवि धूमिल हो गयी। देश की जनता चाहती तो मोदी को है और हिन्दू छवि को महत्व भी देती है लेकिन मतदान करते वक्त उसके भीतर का धर्मनिरपेक्ष वातावरण जागृत हो जाता है और परिणाम अस्पष्ट होने की वजह से सत्तापक्ष स्पष्ट बहुमत नहीं होने का हवाला देकर अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने में जुगाड़ लगाते रहते हैं और विपक्ष यह कहकर जनता को सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका मत अस्पष्ट है तो राजनीति भी कहां से स्पष्ट होगी। 15 अगस्त 1947 का बंटवारा पर सवाल उठने लगा है कि जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र बना तो फिर भारत को हिन्दूराष्ट्र बनने से किसने रोका? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है? क्या अंग्रेजों ने जान-बूझकर कूटनीति करके बंटवारा किया? जब जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार हुए और हो रहे हैं तो भारत में दोहरा चरित्र का राजनीति कौन कर रहा है? देश के बाहर हिन्दुओं पर अत्याचार होने पर विपक्ष धृतराष्ट्र क्यों बन जाती है? क्या भारत में हिन्दू और मुस्लिम के बीच वर्चस्व का जंग जारी हो चुका है? जिस प्रकार जनसंख्या में मुस्लिम वर्ग की वृद्धि और सोसल मीडिया पर यह बयान की 50 साल में भारत देश स्वत: ही मुस्लिम राष्ट्र बन जायेगा सच साबित होगा? क्या भारत में सनातन धर्म पर खतरा मंडरा रहा है? रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की बात के बजाय सिर्फ संविधान की पुस्तक दिखाकर मोदी को घेरना कहां तक उचित है। केन्द्र एवं राज्य की सरकारें अपने मंत्रालय एवं विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय सिर्फ सत्ता की राजनीति को प्रभावकारी बनाकर अपने दल का वारा-न्यारा कर रही है। हत्या, बलात्कार, अपहरण सहित अन्य प्रकार की घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के बजाय जांच एजेंसी को भी राजनीति के चश्में से देखना या उसका इस्तेमाल करने की वजह से आज आवाम को लोकतंत्र में नहीं बल्कि हिन्दू को मंदिरों में विराजमान भगवान और मस्जिदों के मजार पर भरोसा शेष बचा है। जातिवाद के दलदल में धंसता जा रहा भारत एक तरफ विश्वगुरू बनना चाहता है लेकिन अपने ही देश के जातियों में नरसंहार की हालत पैदा करने के लिए कानून भी बनाता है। एक तरफ सबका साथ-सबका विकास की बात होती है और दूसरी ओर जाति-जाति में युद्ध भी। सनातन धर्म में भगवान ने किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया है लेकिन राजनीति ने कानून का हवाला देकर जाति का कुचक्र का वातावरण बनाया गया जिससे लोगों को विश्वास नहीं होता और यही कहकर संतोष कर लेते हैं, भगवान भरोसे है हिन्दुस्तान।

'' हिन्दुस्तान सनातन (देव भूमि) की भूमि है यह सभी धर्मो के जानकार एवं सम्पूर्ण विश्व के प्रशासक जानते हैं लेकिन भारत में एक वर्ग **''हरे कृष्णा - हरे राम''** जप रहा है तो दूसरा वर्ग **''अल्लाह हू अकबर''** की दुहाई दे रहा है, हैरत की बात है कि तीसरा **ओ गॉड** कहकर इसाई धर्म का भारत में धर्म परिवर्त्तन का कूटनीति कर रहा है। इन तीनों की राजनीतिक दंद्ध में हिन्दुस्तान की आवाम गृहयुद्ध की स्थिति झेलने को विवश है और अपने ही अराध्य के प्रति श्रद्धा रखने पर साम्प्रदायिकता का कलंक उसके माथे पर लग जाता है। पूरा विश्व के मानव एवं विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है की सनातन ध र्म सबसे पुराना है और इसके गौरवशाली इतिहास के आज भी प्रमाण जीवित हैं जिसकी पुष्टि **पोथी - पतरा** (पंडित) नहीं बल्कि **रिसर्च एवं पुरातत्व** (वैज्ञानिक) पुष्टि करता है। सत्ता के सिंहासन पर बैठकर रामराज की स्थापना के बजाय कैसे मानवता दूषित हो उसपर कार्य किया जा रहा है। पक्ष एवं विपक्ष हिन्दुस्तान की जनता का क्या सोच है उसपर विचार करने के बजाय आपसी भिड़ंत कैसे बयानों से हो सकती है उसका पुख्ता इंतजाम कर रही है। आजादी के वक्त के बंटवारे की आग धीरे - धीरे सुलग रहा है की धर्म के आधर पर हिन्दुस्तान के टुकड़े हुए।''

दिसम्बर 2024

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

हमारा ई-मेल

आंख सेंकने

संपादक जी,

''**आंख सेंकने के बयान से सीएम नीतीश के चरित्र पर लालू का प्रहार**'' शीर्षक में पत्रकार अमित कुमार एवं त्रिलोकी नाथ प्रसाद ने दिसम्बर 2024 अंक बिहार में प्रगति यात्रा पर सटीक समीक्षा करते हुए खबर लिखा है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के चरित्र पर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति को गरम कर दिया है तथा इस बयान से महिलाओं ने जमकर लालू के विरोध में मोर्चा खोला है। बिहार में बयान का स्तर गिरता जा रहा है।

✦ **प्रवीण भगत, टावर चौक, मुंगेर**

घाटोला

ब्रजेश जी,

आपकी पत्रिका केवल सच का मै नियमित पाठक हूं और इसके सभी खबरों को पढ़ता हूं। स्वास्थ्य विभाग की सभी करतूतों को उजागर करने का काम केवल सच लागतार करता आ रहा है। बिहार के एनएचएम में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला की खबर दिसम्बर 2024 अंक में शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला ने ''आदतन भ्रष्टाचारी हैं कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत'' में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना पर ग्रहण बनकर जनता को बीमार बना दिया गया है। मजबूत एवं सटीक खबर के लिए धनयवाद।

✦ **गणेश यादव, रोड नं-8, राजीव नगर, पटना**

शपथ ग्रहण

मिश्रा जी,

झारखंड चुनाव की सटीक खबरें केवल सच ने लिखा है और गुड्डी साव की दिसम्बर 2024 की खबर ''**हेमंत सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ**'' में चुनाव के नतीजे एवं मुख्यमंत्री पद के साथ-साथ अन्य विभागों के मंत्री ने भी शपथ लिया है की जानकारी इस खबर में लिखा गया है। केवल सच पत्रिका पुलिस-प्रशासन की खबरों के साथ-साथ राजनीति पर भी पूरा फोकस करके खबर लिखा जा रहा है। कई खबरें झारखंड की इस अंक में स्थान प्राप्त किया है। बिहार की तरह विभागों में फैले भ्रष्टचार पर भी पत्रकारों को ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए।

✦ **राजेन्द्र कमलिया, अपर बाजार, राँची, झा०**

बटेंगे-कटेंगे

मिश्रा जी,

दिसम्बर 2024 अंक में आपका संपादकीय ''**राजनीति या सच में बटेंगे तो कटेंगे**'' आपने भारत की राजनीति एवं राजनीतिक दलों की सोच पर काफी रोचक एवं कटाक्षपूर्ण आलेख को लिखा है। जिस प्रकार सत्ता के लिए राजनेता आवाम के बीच धर्म एवं क्षेत्रवाद की हवाला देकर हिन्दू और मुस्लिम की राजनीति को प्रभावकारी बनाया जा रहा है और बटेंगे तो कटेंगे की कूटनीति से देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। आपने पूरी सच्चाई को अपने आलेख के माध्यम से बात रखा है की देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बन सकती है। सटीक संपादकीय।

✦ **रोहन श्रीवास्तव, अस्सी घाट, बनारस, यूपी**

वंशीधर की वंशी

संपादक जी,

तिरहुत स्नातक एमएलसी उप चुनाव के नतीजे पर दिसंबर 2024 अंक में अमित कुमार की खबर ''**तिरहुत में बज गई वंशीधर की वंशी**'' में बिहार की विभिन्न राजनीतिक दलों की जमीनी सच्चाई को केन्द्रीत करके लिखा गया है। एकछत्र राज्य करने वाले क्षेत्र पर वंशीधर का कब्जा होने से यह साबित हो चुका है की इस क्षेत्र में जीत की मुख्य वजह क्या रहती थी और तमाम प्रयास के बाद भी वंशीधर ने सबकी वंशी बजाते हुए जीत का सेहरा अपने माथे पर बांधने में कामयाबी हासिल की है। स्नातक मतदाताओं ने अपने मत का सही प्रयोग किया है प्रतीत होता है।

✦ **मनीष झा, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

बलात्कारी आईएएस

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका के पत्रकारों को भगवान रक्षा करें क्योंकि जिस प्रकार की बेबाक खबर को पाठक एवं सरकार के समक्ष रख रहा है। दिसम्बर 2024 अंक में सोनू यादव की खबर ''**बलात्कारी और भष्ट्राचारी पूर्व विधायक व आईएएस अधिकारी**'' में आपने पूरी घटना को पूर्ण बेबाकी के साथ लिखा है। संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की काली करतूत भी धीरे-धीरे उजागर होने लगा है। बिहार के गौरवशाली इतिहास को अफसरों ने कलंकित कर दिया है। इस अंक की लगभग खबरें आवाम की आँख खोलती नजर आ रही है।

✦ **राजकुमार राम, अशोक नगर, कंकड़बाग**

अन्दर के पन्नों में

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 19, | अंक:- 224, | माह:- जनवरी 2025, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

अविनाश कुमार 7992258137, 9430985773

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

ऋषिकेश पाण्डेय 7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 9470709185

(म०):- गौरव कुमार 9472400626

(ग्रा०) :- मुकेश कुमार 7004761573

बाढ़ :-

भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547

बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

:-

गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :-

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543

नालन्दा :-

:-

नवादा :- अमित कुमार 9162664468

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :-

:-

खगड़िया :-

समस्तीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

वैशाली :-

:-

छपरा :-

सिवान :-

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :-

:-

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649

बगहा :-

मोतिहारी :- संजीव रंजन तिवारी 9430915909

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :-

:- प्रशांत कुमार गुप्ता 6299028442

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपौल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570

नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

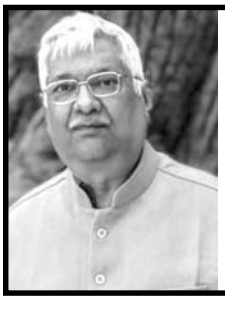

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983,
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा कुमार	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	629970142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

आयोग का हठ छात्रों की जिद्द

पुलिस तंत्र पर नहीं है सरकार का नियंत्रण!

● **अमित कुमार**

आन्दोलन, एक ऐसा शब्द जो अपनी बात को मनवाने और तानाशाही हलफनामे का विरोध का नाम है और भारत में यह अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने को लेकर आन्दोलन होते रहे और अब शासकीय शासन को अपना विरोध प्रकट करने के लिए किये जा रहे हैं। इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। बिहार में तो ऐसा बड़ा आन्दोलन हुआ जो देश की सत्ता को ही डगमगा कर रख दिया और वह आन्दोलन भी छात्रों के द्वारा किया गया। जी हां, बिहार आंदोलन , जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बाद में केंद्र सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गया। इसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। जब नव निर्माण आंदोलन के कारण गुजरात सरकार को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, तब बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो चुका था। नव निर्माण आंदोलन के विपरीत, जनसंघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी युवजन सभा (एसवाईएस) और लोकदल जैसे राजनीतिक छात्र संगठनों ने जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सीपीआई से जुड़ा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) भी इसमें शामिल था। विपक्षी दलों ने 1973 से राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हड़तालियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे 17 अगस्त 1973 को जेपी आंदोलन में भाग लेने के कारण आठ छात्रों की मौत हो गई। रैना जांच आयोग ने भी पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा थी और सरकार ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला था। 18 फरवरी

1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें पूरे राज्य से छात्र नेताओं को आमंत्रित किया गया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार छात्र संघर्ष समिति (बीसीएसएस) का गठन किया और लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष चुना गया। कई समकालीन युवा नेताओं में सुशील कुमार मोदी, नरेंद्र सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और रामविलास पासवान शामिल थे। उनकी मांगें छात्रावासों में शिक्षा और भोजन से संबंधित थीं।

गौरतलब है कि आज एक बार फिर बिहार की धरती पर छात्रों का आन्दोलन जारी है, हालांकि नेता बदल गये हैं। छात्रों के समर्थन में मुख्य रूप से जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हैं तो वही अब छात्रों को सांसद रंजन प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव का भी समर्थन मिल चुका है। इतना ही नहीं छात्रों के समर्थन में प्रख्यात गुरू खान सर और रहमान सर भी खुलकर सामने हैं। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पुनः कराने के मामले में जो सुनवाई होनी थी वह जो टल गई है। जनसुराज और पप्पू यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस ए. एस. चंदेल की एकल पीठ पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधलियों की जांच और पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। बता दें कि जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं, BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। इस अनशन के बीच तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 7 जनवरी को मेदांता अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया था। बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- 'आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए।'

बहरहाल, पूरे मामले को समझते हैं। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं CCE पीटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर पेपर को रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं। ज्ञात हो कि BPSC बिहार प्रशासन में समूह A, B, C पदों को भरने के लिए कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। CCE के माध्यम से BPSC लगभग 20 पदों और सेवाओं के लिए भर्ती करता है। 70वीं CCE परीक्षा के माध्यम से, आयोग का लक्ष्य राज्य भर में 2,035 रिक्तियों को भरना है, जिसके लिए लगभग 3.8 लाख छात्रों ने 13 दिसंबर को BPSC प्रारंभिक परीक्षा दी थी। भारी हंगामे के बाद भी नीतीश सरकार अपने फैसले पर अडिग है और अंतिम फैसला बीपीएससी और राज्यपाल पर छोड़ चुकी है। डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी मीडिया के सामने स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द करने या ना करने का फैसला BPSC लेगी। दरअसल, BPSC

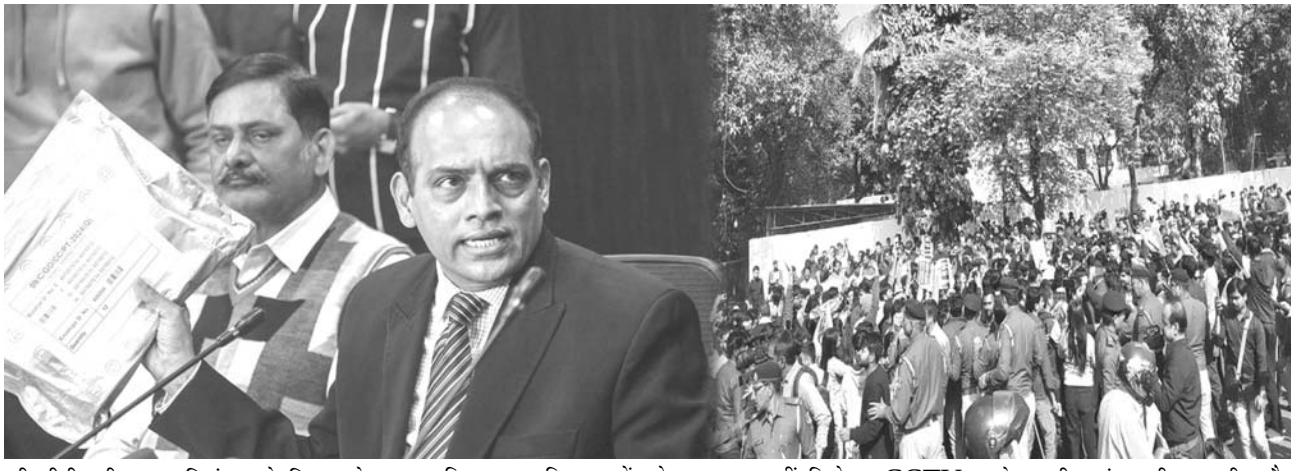

की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार के 912 केंद्रों पर हुई। पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा के दौरान दिक्कतों की शिकायतें मिली। दोपहर लगभग 12:30 बजे, BPSC अधिकारियों को परीक्षा में कुछ छात्रों की ओर से हंगामा करने की शिकायतें मिलीं। हंगामे के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। BPSC अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई के अनुसार, कुछ लोग छात्रों के वेश में प्रश्न पत्र छीनने लगे और चिल्लाने लगे कि प्रश्न पत्र इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसके बाद, परीक्षार्थी प्रश्न पत्रों वाला लिफाफा लेकर परीक्षा कक्ष से बाहर भागे और उसे बाहर इंतजार कर रहे कुछ लोगों को दे दिया। इन परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहर के लोगों की मदद से प्रश्न पत्र को एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि पर अपलोड किया। दोपहर 1 बजे तक, प्रश्न पत्र की कई फोटोकॉपी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रसारित हो रही थीं। बापू परीक्षा भवन से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी ने बताया कि 'मैं परीक्षा दे रहा था, तभी लगभग 12:15 बजे मुझे हॉल के बाहर से शोर सुनाई दिया। खबर सुनकर निरीक्षक ने दरवाजे बंद कर दिए। हालांकि, कुछ मिनट बाद कुछ परीक्षार्थियों ने दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें और प्रश्न हल न करने की धमकी दी।' दूसरे परिक्षार्थी ने कहा कि 'मेरा पेपर छीन लिया गया और मैं परीक्षा नहीं दे सका। मैं दोपहर 1 बजे परीक्षा हॉल से बाहर आ गया।' एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि उसी केंद्र के एक परीक्षा हॉल में लगभग 300 उम्मीदवारों को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। जिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिले, उन्होंने हंगामा किया और मांग की कि किसी को भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि BPSC ने पेपर लीक के आरोप को खारिज कर दिया। उनका दावा है कि जो छात्र 15-20 मिनट से परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रश्नपत्र वायरल हो गया है, जब तक कि वह हंगामा नहीं करना चाहते। इसके बाद BPSC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई परीक्षार्थी, विशेषज्ञ और राजनेता दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी है। वही 13 दिसंबर को, आयोग ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि केंद्र से उपलब्ध CCTV फुटेज की जांच की जाएगी और समस्या पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, बापू परीक्षा परिसर में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के मामले पर 19 दिसंबर को एक पूर्ण-पीठ बैठक हुई। विशेषज्ञों की इस टीम ने बापू परीक्षा परिसर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा रद्द करने और 4 जनवरी, 2025 को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

दिगर बात है कि BPSC ने दावा किया है कि 912 में से 911 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई, लेकिन परीक्षार्थियों का दावा है कि अन्य केंद्रों पर भी समस्याएं थीं। परीक्षार्थी केवल एक केंद्र के लिए BPSC की ओर से दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर भी चिंता जता रहे हैं। उन्हें चिंता है कि इससे स्कोर का सामान्यीकरण वापस आ जाएगा। एक ऐसी प्रथा जिसका BPSC उम्मीदवारों ने पहले विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन 13 दिसंबर से चल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़ गई है। BPSC प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए सैकड़ों उम्मीदवार 18 दिसंबर से

पटना के गर्दनीबाग इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे। वे परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद बैकफुट पर आए आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि वह इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने जा रहा है। आयोग की सफाई के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत तो हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। वहीं, अब बीपीएससी के मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ज्ञात हो कि 6 दिसंबर सुबह के 9 बजे, राजधानी पटना के बेली रोड पर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी के अभ्यर्थी इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। शहर के बीचो-बीच इस तरह के प्रदर्शन की जानकारी होते ही प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने की संभावना को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया और हंगामा जारी रखा। ऐसे में रास्ते को खाली कराने के लिए पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन से रास्ता खाली हो गया और अभ्यर्थी गर्दनीबाग इलाके में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। वही बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद उसी दिन शाम को बिहार के फेमस टीचर खान सर उनके प्रदर्शन में शामिल होने

के लिए गर्दनीबाग पहुंच गए। वहां अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। मैं अभ्यर्थियों का साथ दूंगा। नॉर्मलाइजेशन जब रद्द होगा तब वापस जाएंगे। हम खुद यहीं रहेंगे। हालात पर काबू रखने और कानून-व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने खान सर के साथ ही छात्र नेता दिलीप और एक अन्य कोचिंग संचालक गुरु रहमान को हिरासत में ले लिया था। इन तीनों को ही स्थानीय पुलिस गर्दनी बाग थाने के अंदर लेकर चली गई थी। हालांकि करीब एक घंटे बाद खान सर के साथ अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। दरअसल, खान सर को जब हिरासत में लिया गया, तब वह छात्रों के बीच आंदोलन में ही थे और छात्रों की बातों को सुन रहे थे। इससे पहले खान सर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह छात्रों के हित के साथ हैं और इस पूरे आंदोलन में किसी भी और असमाजिक या माफिया को घुसने नहीं देंगे। खान सर पटना में उन छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। BPSC समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले खान सर ने शुरू से ही BPSC की परीक्षा में कथित रूप से नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने की बात को लेकर के अपना मत जताया था और छात्रों के साथ खड़े हो गए थे।

गौरतलब है कि BPSC परीक्षा में जबसे नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ा है, तबसे ही हंगामा शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर BPSC की परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आसान शब्दों में

कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में दो या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं या सवाल में उनका अटेम्प भी कम रहेगा तो उस पाली को आयोग द्वारा कठिन माना जाएगा। वहीं दूसरी पाली में अगर ज्यादा नंबर आता है और अटेम्प्ट भी ज्यादा होते हैं तो इस पाली को आसान माना जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वालों के नंबर को बढ़ोतरी की जाएगी। इसी बात को लेकर इतना बवाल हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता है, उतना ही जवाब देगा। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 6 दिसंबर देर रात नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात को बेबुनियाद बताया गया। इसके साथ ही आयोग ने एक बार फिर से कंफर्म किया कि परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। इसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने-अपने घर चले गए। वही नॉर्मलाइजेशन का मामला शांत होने के बाद 13 दिसंबर को पूरे बिहार के 912 सेंटरों पर बीपीएसी की परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर दोपहर में ही लीक हो गया था। यह बात जैसे ही फैली अभ्यर्थी हंगामा करने लगे। जिसके बाद अभ्यर्थियों को समझाने के लिए खुद पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह सामने आए। लेकिन हंगामा कर रहे अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और अभ्यर्थियों ने पेपर में धांधली होने का आरोप लगाकर पेपर रद्द करने की मांग शुरू कर दी। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा बापू परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ की घटना के बाद BPSC ने उस केंद्र पर फिर से परीक्षा लेने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान आयोग ने साफ कर दिया कि यह परीक्षा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को देनी होंगी, जिन्होंने बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिया था। दोबारा परीक्षा के लिए आयोग ने 4 जनवरी की तारीख का ऐलान भी कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा को फिर से कराने की मांग कर दी और मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ज्ञात हो कि अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थी 25 दिसंबर शाम 5 बजे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने पहले उनको रोकने का प्रयास किया। ये जब नहीं माने तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को अपराधी की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया।

हालांकि यह सब घटना जिस वक्त हो रही थी, उसी दौरान इस मुद्दे पर पूरे बिहार की राजनीति गरमा गई। सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने परीक्षा में किसी भी धांधली के न होने का दावा किया तो विपक्ष ने पेपर लीक को ही मुद्दा बना दिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर कोई भी पेपर लीक का एक ठोस सबूत लाकर दे देगा तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। वहीं, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन कर दिया। इसी कड़ी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी 24 दिसंबर को छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आयोग छात्रों की मांग नहीं मानी तो 1 जनवरी को पूरे बिहार में बंद होगा। वहीं, जन सुराज ने भी अभ्यर्थियों के मांग का समर्थन करने का ऐलान किया। सनद् रहे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी परीक्षार्थियों का समर्थन किया है और BPSC से नई प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का आह्वान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज करने को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष

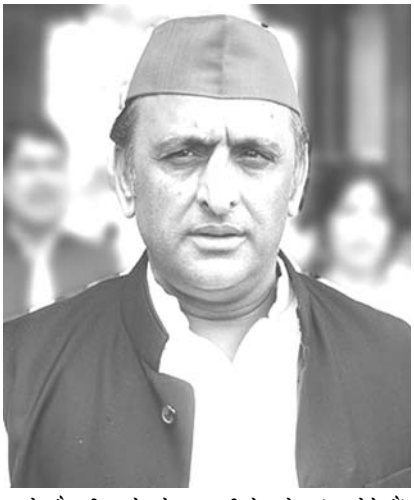

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश सरकार से पांच सवाल पूछते हुए कहा कि क्या बिहार के वर्तमान व भविष्य, बिहार के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करना उनके एवं उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है? क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? क्या सर्वर की गड़बड़ी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के अवसर को फिर से उपलब्ध करवाना असंभव है? क्या पेपरलीक एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? आयोग व सरकार के रवैये को देख क्या अभ्यर्थी यह मान लें कि यह परीक्षा औपचारिकता मात्र है? वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी लगातार अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव इसको लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सवाल उठा चुकी हैं। इसके अलावा वाम दलों ने बिहार के अलग अलग जिलों में ट्रेनें रोककर और प्रदर्शन कर छत्रों के प्रति अपना समर्थन जता चुकी है। अगर सरकार छात्रों की मांगों को नहीं सुनती है, तो मैं छात्रों के विरोध मार्च में सबसे आगे रहूंगा। छात्र लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। वही बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम फिर से दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। फिर वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार या फिर पूरा देश। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां एक सा ही पैटर्न है। कभी डबल शिफ्ट, डबल डे तो कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कभी सर्वर में गड़बड़ी करवाकर, कभी पेपर लीक कराकर, कभी कॉपी बदलवाकर, कभी आरक्षण मारकर, कभी रिजल्ट रोक कर या कभी रिजल्ट को कोर्ट में घसीटकर भाजपा वाले नौकरी पाने के हर तरीके को फंसा देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की मंशा नौकरी देने की होती ही नहीं है। वो हर काम ठेके पर देना चाहती है, जिससे ठेकेदारों से वसूली की जा सके। युवाओं के हक की नौकरियां भाजपा के भ्रष्टाचार का शिकार हो गई हैं. सरकारी नौकरियों को धीरे-धीरे खत्म करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा आरक्षण मारना भी है, क्योंकि ठेकेदारी में आरक्षण लागू नहीं होता है।

बहरहाल, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है। मंत्री सुनील कुमार ने इस मसले को राज्यपाल के पाले में डाल दिया है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बीपीएससी सक्षम प्राधिकार है, वह पूरे मामले में उचित निर्णय लेगा। BPSC छात्रों के डिमांड की स्टडी कर रहा है। उचित समय पर वह अपना निर्णय देगी। लाठीचार्ज की घटना पर मंत्री ने कहा कि एक सीमा होती है कि आप किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, उसको पटना के सीनियर एसपी और

डीएम देख रहे हैं। जहां तक पुनः एग्जाम लेने का प्रश्न है तो बीपीएससी उसपर उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है बयान देने का, लेकिन BPSC ही इस पूरे मामले की जांच करेगा ओर ससमय उचित निर्णय लेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के मुद्दे पर प्रमुख सचिव से अभ्यर्थी की मुलाकात पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने भी अध्यक्ष से बातचीत की है। अब राजपाल के स्तर पर क्या फैसला होता है इसको देखा जाएगा। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ जहां आयोग परीक्षा रद्द नहीं करने की जिद्द पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द की मांग को लेकर छात्र धरना पर बैठे हैं। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसको लेकर छात्रों में उबाल है, तो इसी बीच बिहार सरकार ने इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। पटना में अभ्यर्थियों पर हुई लाठी चार्ज के बाद बिहार की सियासत गर्म है, विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। इस बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वह छात्रों के हित में होगा। हालांकि छात्रों की मांग पर उपमुख्यमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, फैसला आयोग को ही लेना होगा। सरकार ने आयोग को फ्री हैंड छोड़ दिया है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे हैं आरोपों पर भी सम्राट चौधरी ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में ही सभी विभागों पर कंट्रोल रखा जाता था, लेकिन बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से सरकार ने सभी ऑटोनॉमस बॉडी को फ्री हैंड छोड़ दिया है अपने विवेक पर सभी लोग काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट

चौधरी ने बीपीएससी मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और इस पर बात की है, वहीं इसके बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। वही तेजस्वी यादव की ओर से यह कहा जाने पर कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उन्होंने कहा यह बेइमानी वाली बात है। नीतीश कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं और उन्हें समर्थन मिल रहा है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। अभ्यर्थी कई दिनों से पटना में धरना दे रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज के बाद यह बैठक हुई। बातचीत बेनतीजा रही। छात्रों ने अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है। वे पुनर्परीक्षा और दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। BPSC 70वीं PT परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र पटना में धरना दे रहे थे। बीते दिनों पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद, छात्रों के एक समूह ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने अपनी मांगों पर चर्चा की। हालांकि, बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। छात्रों ने अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में अनु कुमारी, राम कश्यप और सुभाष शामिल थे। अनु कुमारी ने कहा, "उन्होंने हमारी सारी बातों को सुना, ऐसा लगता है कि निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में एक पैमाना होता है, निर्णय लेने का। जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के पटना आने के बाद मुलाकात करवाने का भी आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि मुख्यमंत्री के पटना लौटने पर छात्र उनसे मिल सकेंगे। राम कश्यप ने कहा, 'उनका कहना था कि एक केंद्र पर 18 हजार बच्चे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है। इसके बाद मैंने 28 केंद्रों की सूची सौंपी, जिसमें अनियमितता बरती गई। उन्होंने भरोसा दिया है कि अगर इसमें एक भी सच्चाई होगी तो जांचकर पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी।' मुख्य सचिव ने बताया कि एक केंद्र पर 18,000 छात्र थे। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। कश्यप ने 28 परीक्षा केंद्रों की एक सूची सौंपी जहां अनियमितताएं हुईं। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि अगर आरोप सही पाए गए तो जांच की जाएगी और पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुभाष ने कहा, 'जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक धरना जारी रहेगा। मुख्य सचिव को कुछ सबूत भी दिए गए हैं। हम लोगों ने 4 जनवरी की बापू परिसर में पुनर्परीक्षा को स्थागित करने की बात भी कही है तथा छात्रों पर हुए मुकदमा को वापस करने की मांग रखी गई है।' उन्होंने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं होता, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को कुछ सबूत भी सौंपे। छात्रों ने 4 जनवरी को बापू परिसर में होने वाली पुनर्परीक्षा को स्थगित करने और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की थी। यह विरोध BPSC 70वीं PT परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है। वे परीक्षा रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा उन पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना विरोध जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग की तरफ से अब बड़ा बयान आया। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने इस महीने की शुरुआत में हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर विवादों में है। हालांकि, मनुभाई ने यह स्पष्ट किया कि बीपीएससी उन उम्मीदवारों की पुन: परीक्षा कराने जा रहा है, जिन्हें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर केंद्र आवंटित किया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि चार जनवरी 2025 को इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाएगा। बीपीएससी ने हाल में पटना के कुम्हरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी थी, जहां 13 दिसंबर को उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. बीपीएससी के अध्यक्ष मनुभाई ने कहा था कि 13 दिसंबर को आयोजित पूरी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को केवल इसलिए रद्द करने का फैसला किया

क्योंकि परीक्षा को बाधित करने की साजिश के तहत कुछ उपद्रवी उम्मीदवारों ने व्यवधान उत्पन्न किया था। पुनर्परीक्षा चार जनवरी को शहर के किसी अन्य केंद्र पर होगी। उन्होंने बताया कि चार जनवरी की परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने 34 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने में शामिल थे। सभी 34 छात्रों को 26 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आयोग उनके जवाबों की जांच करेगा और उसके बाद उचित निर्णय लेगा। जो लोग अपना जवाब देने में विफल रहते हैं, उनके मामले में आयोग अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा। खास बात ये है कि अभ्यर्थियों का एक समूह राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ एक केंद्र के लिए दोबारा परीक्षा कराना 'समान अवसर' के सिद्धांत के खिलाफ होगा। वही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहले ही धरना स्थल का दौरा कर चुके हैं और आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, पटना जिला प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा कि गर्दनीबाग में 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अधिकांश प्रदर्शनकारी गैर-परीक्षार्थी हैं। उनमें से कुछ ने कथित तौर पर गर्दनीबाग अस्पताल में प्रवेश किया, चिकित्सा कर्मचारियों को परेशान किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। विरोध प्रदर्शन में शामिल तीन लोगों में पूर्वी चंपारण के राहुल कुमार (32), वैशाली के आशुतोष आनंद (35) और सुजीत उर्फ सुनामी गुरु (40) का वर्तमान में पीएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। खान सर के नाम से पहचाने जाने वाले शिक्षक आंदोलन के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने पीएमसीएच में भर्ती अभ्यर्थियों से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने कहा था कि प्रदर्शन का नेतृत्व गैर-परीक्षार्थी कर रहे हैं, जो राजनीतिक कारणों से वास्तविक अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ कोचिंग संस्थान भी इस विरोध प्रदर्शन के पीछे हैं, जिसमें निराधार और भड़काऊ बयानबाजी की गई है, जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करना है। सख्त कार्रवाई के लिए सभी की पहचान की जा रही है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा था कि आज कुछ प्रदर्शनकारी गर्दनीबाग अस्पताल गए और दावा किया कि वे भूख हड़ताल पर हैं और बीमार पड़ गए हैं तथा उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

बताते चले कि छात्रों के समर्थन में उतरे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी BPSC परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच हुई थी। पीके गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें एम्स में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। प्रशांत किशोर को BPSC परीक्षा में बदलावों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे परीक्षा पैटर्न में बदलाव से छात्रों के असंतोष का समर्थन कर रहे थे। पीके कई दिनों से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे, जहां से उन्हें हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा था. प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के बाद पटना एम्स ले जाया गया था, जहां उनके समर्थकों ने खूब बवाल मचाया था। प्रशांत किशोर की गिफ्तारी पर पटना जिला प्रशासन ने कहा था कि प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन ने वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर-कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कई बार आग्रह करने और समय देने के बाद भी जगह खाली नहीं किया गया। इसलिए 6 जनवरी 2025 को उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर पीके की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और हो हंगामा करने लगे। वही जनसुराज पार्टी ने दावा किया कि पटना पुलिस ने पीके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया। इससे पहले गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारे। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद सियासी बवाल होना तय है। बताते चले कि जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी व पटना सिटी की एसपी स्वीटी सहरावत को चेतावनी दे दी। सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने नई-नई नौकरी शुरू की है। मेरा उनको एक सुझाव है कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना है, लोगों को डराना पुलिस का काम नहीं है। यह जो पिछले दो बार से लाठचार्ज हो रहा है और नया हीरो बनने की जो आप कोशिश रही हैं। कहीं ऐसा न हो की आपको ही खामियाजा भुगतना

पड़े। इतना भी वर्दी का रौब मत दिखाइए कि सबकुछ उल्टा पड़ जाए। उनके आदेश पर ही छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। हमलोग पटना सिटी एसपी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग जाएंगे। हमलोग इनपर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे। एक-एक का हिसाब किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि मैं एसपी से डरने वाला नहीं हूं। क्या बच्चों को दौड़ा-दौड़ा कर मारना कानून का उल्लंघन नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह लाठीतंत्र नहीं है। जो अफसर हीरो बन रहे हैं, वह कान खोलकर सुन लें कि साल भर बाद बिहार का निजाम बदलने वाला है। कोई भी बनें लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगें। इसलिए वर्दी का रौब मत दिखाइए। केवल चमकने के चक्कर में वर्दी का रौब दिखाकर बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या आर.के. मिश्रा, आनंद मिश्रा और मैं अपराधी हूं जो बिहार पुलिस ने हमलोगों पर केस किया है? आर.के. मिश्रा डीजी होम रह चुके हैं बिहार में। आनंद मिश्रा एसपी रह चुके हैं। क्या यह लोग अपराधी हैं, जो आप केस कर रहे हैं। हमारी अपील है कि पटना पुलिस इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यह लोग पढ़ने आये हैं देश के भविष्य हैं। आप इन पर लाठी चलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें पढ़ने दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना काफी गलत है। पटना पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन से बौछारें की गई। इसके बाद बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। जिन लोगों ने छात्रों पर लाठी चलाई है। उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे। किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे। इसलिए पुलिस का लाठीचार्ज करना अन्याय है। इधर, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रशांत किशोर पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों से कहा कि वह लोग पांच हजार की संख्या में क्यों आए हैं? जबकि संख्या तीन से चार लाख होने पर सरकार को डराया जा सकता है। इसी बयान के खिलाफ भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर विरोध कर रहे थे। उन सभी छात्रों को प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उकसाया और सरकार को बदनाम करने के लिए विरोध मार्च तक निकालने को कहा। इसलिए पटना पुलिस प्रशांत किशोर पर कड़ी कार्रवाई करे।

ज्ञात हो की पटना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 6 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे बिना शर्त जमानत मिल गई। इससे पहले बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने इनकार दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने लंबी बहस के बाद प्रशांत किशोर को बिना शर्त बेल दे दी। पटना के सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। प्रशांत किशोर को 6 जनवरी की सुबह हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें पटना AIMS में मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। प्रशांत किशोर ने अभी तक बेल बॉण्ड नहीं भरा। अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि प्रशांत किशोर को 25 हजार का बेल बॉण्ड भरना होगा। अदालत के इस बॉन्ड में यह लिखा है कि वह भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शन में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था भंग हो। प्रशांत किशोर ने अदालत से सशर्त जमानत मिलने पर बेल लेने से इंकार कर दिया। प्रशांत किशोर की टीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी रहेगा। युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। वही प्रशांत किशोर के अधिवक्ता व केवल सच पत्रिका के विधि संपादक शिवानंद गिरि ने बताया कि ''बिहार पुलिस ने प्रशांत किशोर जी को झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल भेजने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मुकदमे में यह गाइडलाइन दिया था कि जिस मुकदमे में 7 साल से नीचे की सजा का प्रावधान है। उसमें थाना मुदालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए)(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 35 (3) के तहत) नोटिस भेज कर उनको बांड भरवा कर छोड़ देना है और जब अन्वेषण की समाप्ति हो जाती है और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र जमा करने के लिए प्राप्त साक्ष्य होते हैं तब न्यायालय में समर्पित करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट लेंगे, तब ऐसी स्थिति में आरोपी को न्यायालय से अपना जमानत कंफर्म करवाना होगा परंतु जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के मामले में पुलिस ने ऐसा नहीं किया है।'' वही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जन सुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करने की सबको छूट है, 'क्या सरकार गंगा जल से धुली हुई है?' उन्होंने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन पर खुद कई आरोप लगे हुए हैं और सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। इसे बर्दाशत नहीं किया जाएगा। वही जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर कहा कि उनकी और

उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पूरी तरह जायज है। लोकतंत्र में अराजकता की कोई जगह नहीं है। ये पटना हाईकोर्ट के 2015 के एक आदेश के अनुकूल है। गांधी मैदान धरना की जगह नहीं है। पहले प्रशासन ने उनको चेतावनी दी, नहीं मानने पर ये कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग विवाद को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर एक और कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर ने जो आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसको लेकर अब आयोग की तरफ से प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा गया है। BPSC परीक्षा में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर जब पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे तो उसी दौरान उन्होंने आयोग पर पैसे लेकर सीट पहले ही भेज देने का आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि आयोग ने BPSC की सीटों का सौदा 30 लाख रूपये से लेकर 1.5 करोड़ रूपये तक में कर दिया है और इसी कारण से आयोग परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा नहीं करवाना चाहता है। नोटिस के अनुसार, प्रशांत किशोर ने आयोग पर पिछले दिनों में बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर से आरोप के आधार की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध आईटी अधिनियम आदि में कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। नोटिस में उनके वीडियो के लिंक भी भेजे गए हैं। एक वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के हर जिले में गली मोहल्ले में चर्चा है... बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहां के नेता डील कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए तीस लाख से डेढ़ करोड़ तक लिया जा रहा है। वहीं, दूसरे वीडियो में नौकरियों को 100-150 करोड़, एक-एक करोड़ डेढ़ करोड़ में बेची गई है, ये हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला है...। कुल तीन वीडियो को नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। अब BPSC ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर 7 दिनों के अंदर अपने द्वारा लगाया गया आरोप को सिद्ध करें अन्यथा उनके खिलाफ आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा। BPSC के तरफ से कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा गया है कि अगर प्रशांत किशोर ने आयोग पर लगाए गए आरोप को 7 दिनों के अंदर साबित नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्होंने आयोग की छवि को धूमिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। वही आयोग का आईटी सेल इंटरनेट ने मीडिया पर आयोग के विरुद्ध की गई तथ्यहीन बयान से संबंधित दजर्नों वीडियो को सर्च किया है। इसमें कई कोचिंग संचालक, शिक्षक, विभिन्न दलों के नेता, विधायक, एमएलसी आदि आयोग की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार आयोग संवैधानिक संस्था है। इससे लाखों परीक्षार्थियों का भरोसा जुड़ा होता है। तथ्यहीन आरोप लगाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। पूरी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी को नोटिस भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी के खिलाफ अनशन पर थें। बीते दिनों तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना स्थित मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। वहीं, 9 जनवरी को को उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पीके की हालत में सुधार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पटना के मरीन ड्राइव (गंगा किनारे) पर सत्याग्रह करने की अनुमति मिल गई है। ये परमिशन 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों के विरोध में उनके सत्याग्रह के लिए दी गई है। जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ यह अनुमति प्रदान की है। इससे पहले बिना अनुमति टेंट लगाने पर रोक लगा दी गई थी। पीके जल्द ही मरीन ड्राइव पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। बीपीएससी मामले में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एंट्री मारी थी, मगर बहुत जल्द किनारे हो गए। इसके बाद पप्पू यादव ने इसे लेकर बिहार बंद कराया। मगर, प्रशांत किशोर इस मामले को लेकर अब तक डटे हुए हैं। पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में कई दिनों से प्रशांत किशोर सत्याग्रह कर रहे हैं, अब मरीन ड्राइव पर गंगा किनारे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पटना के जिलाधिकारी ने उन्हें यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी।

इससे पहले, प्रशांत किशोर बिना अनुमति के मरीन ड्राइव के पास टेंट सिटी बनवा रहे थे। जिला प्रशासन ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया था, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को पत्र लिखकर इस रोक को हटाने की मांग की थी। डीएम ने मामले में हस्तक्षेप किया और पीके को सत्याग्रह की अनुमति दे दी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप मुख्य कारण है, जिसके विरोध में पीके यह सत्याग्रह कर रहे हैं। वे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब प्रशासन ने अनुमति दे दी है, तो पीके जल्द ही मरीन ड्राइव पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। कोर्ट से बेल मिलने के बाद, प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव पर बड़े स्तर पर सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे। टेंट सिटी बनाने का उद्देश्य बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करना था। हालांकि, प्रशासन ने बिना अनुमति के निर्माण को रोक दिया। अब, प्रशासन द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ, उन्हें मरीन ड्राइव पर सत्याग्रह करने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन खत्म हो गया है, अब वो जनसुराज आश्रम में सत्याग्रह कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव तक आश्रम से ही वो अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करेंगे। गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने गंगा में डूबकी लगाई, और फिर आश्रम में हवन के साथ अपने अनशन को पूर्णाहूति दी। प्रशांत किशोर की ये अदा जनसुराज पार्टी की भविष्य की राजनीतिक लाइन की तस्वीर काफी हद तक साफ कर देती है। फिर भी, पहले ये देखना होगा कि गांधी से गंगा तक के अपने हालिया राजनीतिक सफर में प्रशांत किशोर ने क्या पाया और क्या खोया है? 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से आमरण अनशन शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने 16 जनवरी को गंगा में डूबकी लगाकर अपना अनशन तोड़ दिया। BPSC परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के हाथ से केला खाने और जूस पीकर अनशन खत्म करने से पहले प्रशांत किशोर ने गंगा किनारे बने अपने नये नवेले आश्रम में हवन भी किया, जहां जय बिहार और भारत माता की जय के नारे लगाये जा रहे थे। प्रशांत किशोर का नया कैंप ऑफिस जिसे आश्रम नाम दिया गया है, अभी निर्माणाधीन है। जनसुराज की तरफ से गंगा किनारे निजी जमीन पर प्रशांत किशोर के लिए कैंप ऑफिस बनना शुरू हुआ, तो प्रशासन ने रोक लगा दी थी लेकिन, बाद में अस्थाई कैंप बनाने की अनुमति दे दी गई। बताया गया है कि प्रशासन की अनुमति और जमीन मालिक को किराया देने के बाद मौजूदा व्यवस्था से पीड़ित लोगों के लिए ये आश्रम को बनवाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें गांधीजी की प्रतिमा के नीचे से हटाया गया था, और अब हम गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं। लोकतंत्र की जननी को लाठीतंत्र नहीं बनने देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने और कराने वाले अफसरों को वो कोर्ट और मानवाधिकार आयोग तक लेकर जाएंगे। अनशन शुरू होने से पहले प्रशांत किशोर अचानक विवादों में आ गये थे। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन से पहले मौके से भाग जाने के लिए वो निशाने पर तो थे ही, कंबल देने के लिए एहसान जताने वाला उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया था, लेकिन आमरण अनशन, जमानत की जगह जेल भेजने की बात और अब सत्याग्रह के जरिये वो अपने खिलाफ हुए सारे विवादों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक सफल भी लगते हैं और अब आगे की राजनीति को सत्याग्रह बता रहे हैं। जन सुराज अभियान की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहे हैं, और सत्याग्रह भी उनके खिलाफ ही होगा। पॉलिटिक्स में पब्लिसिटी और ब्रांडिंग का भरपूर इस्तेमाल

करने वाले प्रशांत किशोर ने मार्केट में जन सुराज नमक भी उतार दिया है। जन सुराज आश्रम के पास ही एक वैन पर सेंधा नमक बेचा जा रहा है। कलर स्कीम भी जन सुराज वाली ही नजर आती है, ये पैकेट भी पीले रंग का ही है। एक पैकेट के लिए MRP 60 रुपये रखा गया है, लेकिन जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये 50 फीसदी छूट के साथ 30 रुपये में दिया जा रहा है। सुनने में आया है कि नमक के साथ लोग आटा की भी डिमांड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने आंदोलन को महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहेब आंबेडकर से प्रभावित बताते हैं, और समझाने की कोशिश करते हैं कि जन सुराज का सत्याग्रह भी वैसे ही है, जैसे नमक आंदोलन शुरू किया गया था। ये बात अलग है कि नमक सत्याग्रह के नाम पर नमक बेचा जा रहा है। अब तक प्रशांत किशोर बेली रोड के शेखपुरा हाउस में रह रहे थे, एक पूर्व सांसद का पुश्तैनी मकान है। जिस वैनिटी वैन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, वो भी पूर्व सांसद की ही बताई गई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आने वाले कई महीने वो आश्रम में ही रहेंगे और वहीं से सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। मीडिया से बातचीत में कहते हैं, आश्रम से आज ही से सत्याग्रह की शुरुआत हो गई है, मैं यहीं पर रहूंगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक उनका सत्याग्रह बिहार के उन लोगों के लिए है, जो व्यवस्था से परेशान हैं। जो बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है, गांधी जी की मूर्ति के नीचे से हटाया गया था, अब हम गंगा जी की गोद में बैठ गये हैं। सरकार हमारी आवाज नहीं दबा सकती। गांधी जी की मूर्ति से आवाज दबाया गया तो गंगा जी से आवाज निकलेगी। अब यह देखना होगा कि आगे स्थिति कैसी रहती है और पीके का सत्याग्रह कितना प्रभावी साबित होता है। प्रशांत किशोर का यह कदम बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। वही दूसरी ओर लोक सभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। जहां BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। करीब एक महीने से जारी इस आंदोलन में लाखों युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के दौरान, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया और राज्य सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग की। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुए कथित धांधली और परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव रहा, और इसके परिणामों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका पार्टी इस संघर्ष में अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और उनकी मांगें पूरी होने तक उनका समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभाव से इस मामले में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहुल गांधी को पुलिस की बर्बरता के वीडियो क्लिप्स भी दिखाया, जो पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज को दर्शाते हैं। 'राहुल गांधी ने कहा कि आपका भाई, आपके साथ खड़ा है। छात्रों ने राहुल गांधी से इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की। उन्हें बताया कि पिछले एक महीने से किस तरह से लाठियां खाकर भी प्रदर्शन जारी है। वही BPSC आन्दोलन में एक नयी बात देखने को मिला। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। उन्हें कई राजनेता, शिक्षकों और कोचिंग संचालको का भी सहयोग मिला हुआ है। उनके समर्थन में शिक्षक गुरु रहमान भी उतरे हुए हैं। उन्होंने छात्रों के समर्थन में अनोखा कदम उठाया है। गुरु रहमान ने अपने हाथ की नसों को काटकर अपने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई है। गुरु रहमान ने कहा है कि वह छात्रों के हित के लिए हमेशा अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। चूंकि मामला कोर्ट में भी है और उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग कोर्ट में सुनवाई के लिए तय की गई तारीख के पहले ही अपने परिणाम को जारी करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में हमारी कोशिश यह है कि हम अपनी गुहार को इन लोगों के सामने रखें, ताकि इस मामले में हमारे साथ न्याय हो सके। गुरु रहमान का यह भी कहना था कि जब देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए पहल की गई थी, तब भी उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के धारा 370 को हटाने का समर्थन किया था। ऐसे में उनको पूरा विश्वास है कि इस बार भी जब वह छात्र हित में अपने खून से पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री उस पर जरूर ध्यान

देंगे। उनका कहना है कि वह हमेशा से ही छात्रों के हित को लेकर लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर उनके पक्ष में यह फैसला नहीं आता है तो वह पूरे बिहार का दौरा करेंगे और छात्रों को जागृत करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि कई तरह का विज्ञापन होता है, जिसमें नीचे लिखा मिलता है-शर्तें लागू। कुछ इसी तरह से बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्राथमिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया है। आगे बढ़ने के पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें-'एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका CWIC-369/2025 में पारित आदेश के फलाफल से परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रतिवारित किया गया है एवं भविष्य में प्रतिवारित किया जाना है उनकी भी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।'

बहरहाल, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुद्दों को गरमाने के जतन किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें चूकना नहीं चाहतीं। बिहार लोक सेवा आयोग भी इसी वजह से निशाने पर है और 18 वर्षों से शासन कर रहे नीतीश कुमार ने इसे अनदेखा करते हुए आयोग को निशाना बनने भी दिया। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनकी मांग है पूरी पीटी परीक्षा रद्द करने की। उनका कहना है कि एक एग्जाम हो और एक साथ नतीजे आएं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाकर विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्ष मामले को अलाव बनाकर हाथ सेंकना चाहता है। कड़ाके की सर्दी में धरना- प्रदर्शन करते BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से मुद्दे को मिली गर्माहट राजनीतिक दलों को रास आ रही है। बीते दिनों विपक्षी विधायकों का राजभवन मार्च रास्ते में रोक दिया गया तो वे राज्यपाल से मिलने पर अड़ गए। कोशिशें जारी हैं कि आंदोलन का रूप देकर युवाओं की भावनाएं भड़का दी जाएं और चुनावों से पहले छात्रों-युवाओं की सहानुभूति का लाभ भुना लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक हाथ में नहीं है। परीक्षा के पहले आयोग कार्यालय पर छात्रों का नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन ही इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। आयोग की ओर से पहले ही बता दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। फिर भी, इसे लेकर उग्र विरोध-प्रदर्शन किया गया और तब पुलिस की लाठियां प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसीं। फिर पेपर लीक की अफवाह और हंगामा। इसके बाद एक-एक कर राजनेताओं की एंट्री। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया। सारी बातों से साफ होता है कि आंदोलन खड़ा कर फायदा उठाने की कोशिश चल रही है। राज्य सरकार ने भी इन इरादों को पनपने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई यह बताती है कि सरकार में बैठे लोगों का पुलिस तंत्र पर नियंत्रण नहीं रह गया है। स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाठी चलाने की नौबत आती। इससे यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि जान बूझकर ऐसा कराया गया और ऐसे लोग तंत्र पर हावी हैं, जो इस मुद्दे को तूल देना चाहते हैं। सरकार चाहती तो शुरुआत में ही समाधान का इरादा जताकर आंदोलन भड़कने से रोक सकती थी। जब समस्या सिर चढ़ी, तब परीक्षार्थियों के प्रतिनिधियों की मुख्य सचिव से वार्ता हुई। फिर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बयान दिया कि सरकार जल्द ही समाधान निकाल लेगी। सम्राट चौधरी का यह कहना भी मुद्दा बनाओ अभियान का हिस्सा है कि एनडीए सरकार आयोग की स्वायत्तता में दखल नहीं देती, जैसा पिछली सरकारें करती आई हैं और अपना निर्णय उस पर थोपती रही हैं। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। 2023 में भी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला प्रकाश में आया था। 56वीं और 59वीं परीक्षा में भी गड़बड़झाले हुए थे। तब घूस लेकर डीएसपी बनाने का केस खुला था और मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजेपी के विधान पार्षद रहे आयोग के सदस्य रामकिशोर सिंह 30 लाख रुपये लेकर नौकरी देने के मामले में घिरे थे। 2017 में लेक्चरर की बहाली में खूब अनियमितता हुई। ऐसे अभ्यर्थी भी चुन लिए गए थे, जिनके पास निर्धारित पात्रता नहीं थी। यहां तक कि इंटरव्यू नहीं देने वाले भी सिलेक्ट हो गए थे। BPSC के साथ जुड़े विवादों की लिस्ट यहीं नहीं थमती। 2003 हो या 2005- गलत चयन, घोटाले और अनियमितता के मामले सामने आते रहे। आयोग की पूर्व अध्यक्ष रजिया तबस्सुम सहित 13 अधिकारियों पर आरोप तय हुए थे। एक अध्यक्ष राम सिंह आसन सिंह को भी विवादों के चलते पद से हटाया गया था। ऐसा भी हुआ कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने और पैसे के लेन-देन के प्रमाण मिले। साल 1996 में तो इंजिनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का बड़ा घोटाला हुआ था, तब जांच की आंच तत्कालीन विज्ञान व प्रावैधि की मंत्री बृजबिहारी प्रसाद तक पहुंची थी। उस घोटाले में तत्कालीन आयोग अध्यक्ष लक्ष्मी रंगत को जेल की हवा खानी पड़ी थी। इनमें कई विवाद तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए। सच कहा जाए तो BPSC सरकारी संरक्षण में नौकरी बेचने वाले एक गिरोह तंत्र की माफिक काम करने के लिए कुख्यात रहा है! आज भी आयोग धरना-प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है। शायद ही कोई बहाली और परीक्षा परिणाम बिना विवाद के रहे हों। नीतीश कुमार बेशक भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा दें, लेकिन लोक सेवा आयोग की कथाएं इसे झुठला देती हैं। ताजा विवाद भले मुद्दा निर्माण का हो, लेकिन इसे पनपने तो नीतीश सरकार ने ही दिया।●

अपराधियों पर नकेल कसना मेरा मुख्य टार्गेट : के. रामदास

आए दिन बिहार में लगातार अपराध एवं अपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती जा रही हैं, जिसमें राजधानी पटना भी अछूता नहीं हैं। सुशासन सरकार की पुलिस अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं फिर भी जहाँ पुलिस बल कमजोर दिख रही हैं वहाँ सुलझे हुए पदाधिकारी की पोस्टिंग कर वरीय पदाधिकारी द्वारा लगातार मॉनेटरिंग जारी हैं ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे अपराधियों की मंसूबों पर पानी फेरा जा सके साथ ही साथ मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी योजना शराबबंदी को फेल करने में लगे माफियाओं पर नकेल कसते हुए उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। फिलवक्त अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ एसएसपी के साथ चार नए युवा सिटी एसपी,तीन नए युवा आईपीएस एएसपी के रूप में तो वहीँ एसडीपीओ के रूप में कई तेज तर्रार पदाधिकारी लगाए गए है ताकि राजधानी वासी सुरक्षित एवं शांति के माहौल में रह सके। पटना सिटी एसपी पूर्वी की जिम्मेदारी एसएसपी के बाद काफी महत्वपूर्ण एवं चुनौतिपूर्ण हो जाती हैं ।यह क्षेत्र काफी बड़ा होने के साथ साथ शहरी एवं ग्रामीण मिश्रित आबादी का क्षेत्र हैं। एसपी पूर्वी की चर्चा आज आमलोगों में काफी तेज हो गई है क्योंकि लोगों की समस्याओ को सुनना एवं त्वरित कार्रवाई के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश देना, पीड़ितों को पुलिस के प्रति एक भरोसा स्थापित होते दिख रहा हैं। पटना के सिटी एसपी पूर्वी डॉ के रामदास से पत्रिका प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** के साथ **मुकेश कुमार** ने खास मुलाकात की जिसके संपादित अंश :-

★ बतौर आईपीएस बिहार सरकार एवं यहाँ की पुलिस व्यवस्था आपको कैसी लगी?

मैं 2019 बैच का बिहार कैडर का आईपीएस हूँ। जॉइन करने के उपरांत रोहतास के बिक्रमगंज में जिला ट्रेनिंग हुआ उसके उपरांत गया के शेरघाटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में दो साल कार्य किया उसके बाद एसपी सिटी भागलपुर और अभी पटना के एसपी सिटी पूर्वी की भूमिका में कार्य कर रहा हूँ। बिहार सरकार एवं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ है। यहाँ कार्य करने का काफी स्कोप हैं। वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन और जूनियर लोगों के साथ टीम वर्क के रूप में हमलोग कार्य करते है।

★ अलग-अलग जगह पर कार्य करने का अनुभव कैसा रहा?

हर जगह कार्य करने का अपना एक अलग अनुभव रहा हैं। रोहतास एवं शेरघाटी थोड़ा नक्सल समस्याएं दिखने को मिलती है। भागलपुर में स्नैचिंग तो पटना में विधि व्यवस्था को लेकर हमलोग टीम वर्क के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। हमारा मानना है कि अपराध छोटा हो या बड़ा करने वाला अपराधी ही है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

★ अनुसंधान करते वक्त किन तथ्यों को ध्यान मे रखते है ताकि कोई निर्दोष दोषी होने से बच सके?

क्राइम इनवेस्टिगेशन साइंटिफिक इनवेस्टिगेशन से हो रहीं है। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक सबूत का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपराध में फॉरेंसिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है ताकि कोई आरोपी बच न सके और निर्दोष दोषी होने से बच जाए।

★ बतौर एसपी सिटी पूर्वी आपकी प्राथमिकता क्या है?

हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति त्वरित एवं उचित न्याय से वंचित नहीं हो। क्राइम कन्ट्रोल हमारी प्राथमिकता में है। महिलाओं एवं बच्चे की समस्याओं के निदान के लिए थाने में अलग से महिला पदाधिकारी नियुक्त है। कोई भी पब्लिक थाने में अगर आवेदन देता है तो उसे हर हाल में पावती रसीद मिलना चाहिए। पेंडिंग केश का निष्पादन ससमय हो और विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले चाहे कोई भी हो उनपर त्वरित करवाई होगा।

★ अपने अधीनस्थ कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि थाने स्तर से पब्लिक के प्रति व्यवहार बेहतर हो?

आज के समय मे पुलिस पब्लिक मैत्रेयी सम्बन्ध बेहतर होते जा रहा हैं। महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के लिए अलग से कार्य कर रहीं है। 8 कोई भी आवेदन अगर एफआईआर और नॉन एफआईआर कम्प्लेन रजिस्टर मे दर्ज कर उसका रिसीविंग आवेदनकर्ता को सौंपे। क्राइम मीटिंग में भी कम्यूनिटी पुलिसिंग पर जोड़ दिया जाता रहा हैं।

★ क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वह भयमुक्त होकर रह सके एवं पुलिस के कार्यो मे मदद कर सके?

कोई भी पब्लिक अगर थाने में अगर आवेदन देने आते है तो उनके आवेदन पर विधि सम्मत करवाई होगी। आवेदन के साथ उसका रिसीविंग जरूर मिलेगा। उनके आवेदन पर निष्पक्ष एवं त्वरित करवाई होगी। हमलोग मैत्रेयी सम्बन्ध के साथ कार्य करना चाहते हैं। कोई भी समस्या आपके बीच से ही उत्पन्न होकर समाज में फैलती है अगर इसकी सूचना आप पुलिस को त्वरित करते है तो समय रहते ही उस समस्याओं पर नकेल कसा जा सकता हैं। सारे पदाधिकारियों के नंबर सार्वजनिक हैं थाने स्तर पर अनुमंडल स्तर पर या मुझे भी सूचना देकर किसी बड़ी

भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करती है भाजपा

आदतन भ्रष्टाचारी सुहर्ष भगत को स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर पुरस्कृत किया

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने वाली एजेंसी का मुखिया ही जब अपनी जेब का स्वास्थ्य सही करने में लगे तो क्या होता है यह दिखा 15 जनवरी 2025 बुधवार को बापू सभागार पटना में, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भ्रष्टाचारियों सुहर्ष भगत को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। यूं तो स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2024 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों/पदाधिकारी/कर्मियों को सम्मानित करने के लिए यह सम्मान समारोह था, लेकिन पुरस्कार चयन का क्या आधार था यह तो सिर्फ मंत्री महोदय ही बता सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने 2024 के अपने कार्यकाल में 102 एंबुलेंस कर्मियों को वेतन नहीं दिया ,जबरन वसूली करने वाले एंबुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जैन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को सर माथे बैठा कर रखा। पैथोलॉजी सेवा प्रदाता के निविदा में L2 र को GFR, BFR और सीबीसी के नियमों के खिलाफ L2 पर ही L1 घोषित कर दिया, CHO परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुहर्ष भगत का नाम आने के बाद जाँच ही बंद करवा दिया। इन बेहतरीन कारनामो के लिए सुहर्ष भगत को स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार की गति आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रंगारंग कार्यक्रम के बीच 2024 के उत्तम भ्रष्टाचारी पुरस्कार से स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया।

सम्मान समारोह में कुछ मेहनती अधिकारियों को भी आई वास करने के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें एक नाम सहायक निर्देशक राज्य स्वास्थ्य समिति मनीष रंजन का भी है, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर बिहार में अकेले मुफ्त दवा योजना को राज्य के कोने-कोने तक फलीभूत करवाया। उन्होंने असीम ऊर्जा के बल पर देर रात अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर मुफ्त दवा योजना की मॉनिटरिंग की और उसे पूरे राज्य में नियमित करवाया।

सरकार ने उनकी इसी ऊर्जा शक्ति को देखते हुए उन्हें कार्यालय सहायक से सहायक निर्देशक भी बना दिया। और कई नाम हैं, जिनको सम्मान देकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी लाज बचाई, लेकिन अधिकतर नाम ऐसे हैं जो चाटुकारिता या रिश्वत के पैसे को ऊपर तक पहुंचाने के कारण मिला है, जिसमें सुहर्ष भगत और प्रिय रंजन राजू जैसे नाम प्रमुख है। मैं इस आलेख के माध्यम से ऐसे दर्जनों नाम का खुलासा कर सकता हूं जिनको सिर्फ चाटुकारिता या रिश्वत की राशि ऊपर तक पहुँचाने के कारण पुरस्कृत किया गया है, लेकिन मेरे दृष्टि में अभी यह सही नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर अगले अंक में हम उन नामों पर चर्चा जरूर करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी संघ सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी संघों ने इस सम्मान समारोह में चाटुकारिता के दम पर पुरस्कार देने की कड़ी भतर्सना की है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक संघ के पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर कहा कि आजकल पुरस्कार के नाम पर धंधा चल रहा है। आज हम भी पैसा दे दें तो हमें भी पुरस्कृत किया जा सकता है। सारा खेल पैसों का है।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कार्य सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना होता है, जिसमे सीएचओ अधिकारी समुदाय में फैलने वाले संक्रामक रोगों, महिला देखभाल आदि का सही आकलन कर आवश्यकतानुसार उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में उनकी मदद करते हैं, इनका कार्य हमारे कम्युनिटी में फैलने वाले संक्रमण जनित बीमारियों आदि पर नजर बनाये रखना होता है और उनको दूर करने के लिए समस्त सरकारी सुविधाओं को रोगीयों तक आसानी से सुलभ करवाना होता है।

CHO परीक्षा रद्द होने के बाद बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सॉल्वर गैंग ने 4-5 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पास कराया। आर्थिक अपराध इकाई ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सेंटर सुपरिटेंडेंट और आईटी हेड शामिल हैं। रिमोट सॉफ्टवेयर से सॉल्वर्स ने कंप्यूटर कंट्रोल कर सवाल हल किए। पेपर लीक की अटकलों के बीच समिति ने इस परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की टीम ने रविवार, 1 दिसंबर को 12 ऑनलाइन केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान परीक्षा के लिए बनाए गए ऑनलाइन सेंटर्स पर गड़बड़ी के कई साक्ष्य के मिले थे। इसी वजह से इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि जिन सेंटरों को पहले से संदिग्ध माना जा रहा था, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक पेपर लीक मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। रामकृष्णा नगर में स्थित कई सेंटरों से 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, दो सेंटरों को सील भी किया गया है। बता दें कि इस परीक्षा के पहले कुछ संबंधित ऑडियो और वॉट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी,

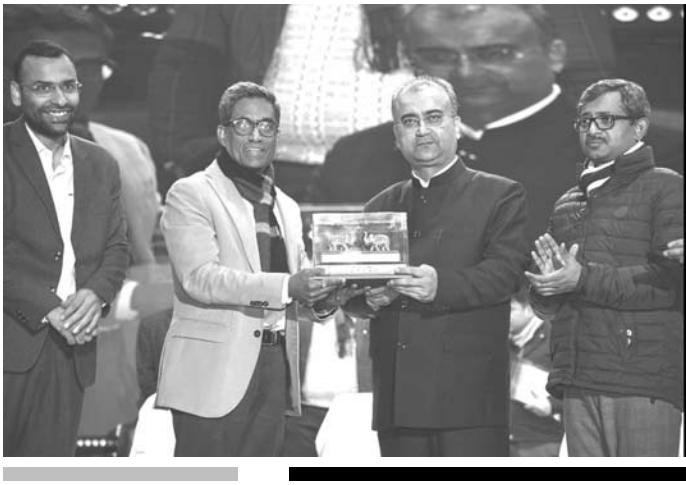

जिसके बाद पटना पुलिस ने कुछ सेंटर्स पर छापेमारी की थी।

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) को की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कई गिरफ्तारियां भी की गई थी। कुछ दिनों तक जांच और गिरफ्तारी भी तेजी से हो रही थी, लेकिन जैसे ही राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक महोदय सुहर्ष भगत (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का नाम इसमें आया तो जांच को शिथिल या बंद कर दिया गया। केवल सच ने इस सम्बन्ध में जब पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, आर्थिक अपराध इकाई और केश के अनुसंधानकर्ता पुलिस उपाधीक्षक संजीत कुमार सिन्हा से लगातार दिनांक-16/01/2025 और 17 /01/2025 को मिलकर पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। तब हमने पत्र के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, आर्थिक अपराध इकाई से कुछ बिन्दुओ पर उनका पक्ष जानना चाहा :-

(1) क्या जांच बंद कर दी गई है या शिथिल कर दी गई है?

(2) क्या जांच के क्रम में अपराधियों/शिक्षा माफियाओं द्वारा कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति सुहर्ष भगत का नाम लिया गया था?

(3)क्या जांच के क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक महोदय सुहर्ष भगत के अधिकारियों या राज्य स्वास्थ्य समिति को दोषपूर्ण प्रणाली सामने आया था।

(4) क्या राज्य स्वास्थ्य समिति के किसी अधिकारी से इस संबंध में पूछताछ की गई है?

(5) क्या मुख्य सरगना रवि शंकर और सुहर्ष भगत के फोन लोकेशन अथवा फोन से बातचीत की जांच की गई है?

केवल सच का आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में लगातार जाने से जाँच में फिर से सुगबुगाहट आयी और EOU ने सील परिक्षा केंद्र को खोलकर सबूत खोजने की निरर्थक कोशिश की गयी।

"घोटालों का बादशाह"

निविदा की कागजी दुनिया में, छिपे साजिशों के तार,
सुहर्ष भगत के काले खेल, बने जनता के गुनाहगार।
एम्बुलेंस की सेवा लूटी, दर्द में जो थे बेबस,
चुनकर आए इस भ्रष्टाचार के, खुद को साबित किया अहम।
पैथोलॉजी की निविदा में, खेला ऐसा खेल,
मानवता को बेचा जिसने, वो बना भ्रष्टाचार का मेल।
मानव बल की बोली लगाई, मेहनत की कीमत चुराई,
हर मोर्चे पर काली करतूत, सच्चाई को हर बार हराई।
आदतन जो हो भ्रष्टाचारी, उसको कौन समझाए?
जनता का हक छीनकर भी, उसको नींद कैसे आए?
घोटालों का ये बादशाह, हर दिन नई चाल रचता,
पर सच के आगे, एक दिन उसका भी सिंहासन ढहता।
सुहर्ष भगत, सुन लो ये बात, जनता जागेगी एक दिन,
सच के दीप जलेंगे जब, तुम्हारी काली रात बुझेगी फिर।
कागज के महल जो बनाए, वो तूफान से उड़ जाएंगे,
भ्रष्टाचार की ये काली छाया, हमेशा के लिए मिट जाएंगे।

CHO परीक्षा में गड़बड़ी का जाल

धोखाधड़ी की दास्तां
चुनाव का सपना, रोजगार का वादा,
जुबां पर था सच, दिल में था फसादा।
स्वास्थ्य के नाम पर जो खेल रचा,
बेरोजगारों के सपनों को कुचला।
सुहर्ष भगत की कुर्सी का फर्ज,
बना लालच का एक और मर्ज।
CHO परीक्षा में गड़बड़ी का जाल,
न्याय के मंदिर में किया सवाल।
किसने दिए उन्हें ये काले हाथ?
जो छीन लें मेहनतकश की बात।
बेरोजगारी के दर्द पर नमक छिड़का,
सच के नाम पर झूठ का झगड़ा।
करोड़ों कमाने की थी जो चाल,
सच का दम तोड़ने का हाल।
पर अब उठेंगे सवाल हर ओर,
करेगा न्याय, फूटेगा जोर।
यह धोखा नहीं, यह कायरता है,
जनता की आवाज ही ताकत है।
लालच का अंधेरा अब दूर होगा,
हर सपना फिर से जरूर पूरा होगा।

केवल सच पत्रिका का मुख्य काम भ्रष्टाचार के बुनियाद को हिलाना है। इसी उद्देश्य से हमने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर केंद्र और राज्यों को पत्र लिखा था और बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से जांच करने को कहा, लेकिन यहां तो डाल–डाल पर भ्रष्टाचारी रूपी सांप डसने को तैयार है, इसलिए जांच होने वाली तो नहीं है।

Under the Public Grievances redressal System of Govt. of Bihar. The following Pending Application Received on the Department email.

Forwarded for your kind perusal and necessary action.

Sl. No.	Departmental Dairy No./Date	Applicant Name	Applicant email ID
1-	3783/24	श्री शशि रंजन सिंह सहायक संपादक	shashiranjan3@gmail.com

The applicant should also be Kindly informed about the action taken and copy to the Public Grievances Cell] General Administration Department] Bihar] Patna. Public grievances Bihar (GAD)

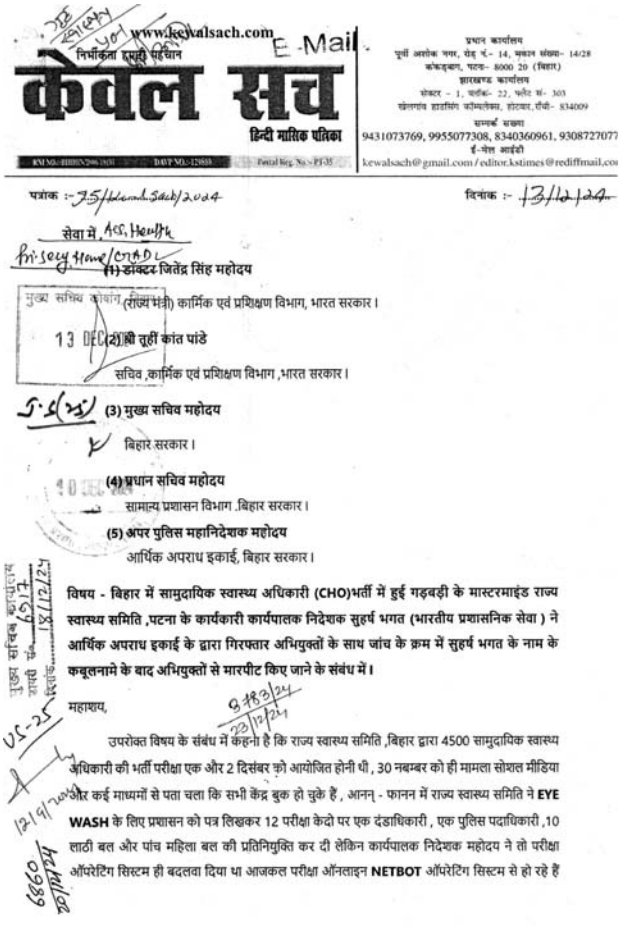

पेथोलोजी की सेवाएं सभी सवास्थ्य केंद्र पर मुहैया करने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की गयी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका
प्रधान कार्यालय
सम्पर्क सख्या
9431073769, 9955077308, 8340360961, 9308727077
ई-मेल आईडी
kewalsach@gmail.com / editor.kstimes@rediffmail.com

पत्रांक :- 75/Kewal Sach/2024 दिनांक :- 13/12/24

सेवा में, ACS, Health
Pri. Secy. Home/GAD

(1) डॉक्टर जितेंद्र सिंह महोदय
(राज्य मंत्री) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार।

(2) श्री तूहीं कांत पांडे
सचिव ,कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ,भारत सरकार।

(3) मुख्य सचिव महोदय
बिहार सरकार।

(4) प्रधान सचिव महोदय
सामान्य प्रशासन विभाग .बिहार सरकार।

(5) अपर पुलिस महानिदेशक महोदय
आर्थिक अपराध इकाई, बिहार सरकार।

विषय - बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)भर्ती में हुई गड़बड़ी के मास्टरमाइंड राज्य स्वास्थ्य समिति ,पटना के कार्यकारी कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत (भारतीय प्रशासनिक सेवा) ने आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ जांच के क्रम में सुहर्ष भगत के नाम के कबूलनामे के बाद अभियुक्तों से मारपीट किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ,बिहार द्वारा 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती परीक्षा एक और 2 दिसंबर को आयोजित होनी थी , 30 नबम्बर को ही मामला सोशल मीडिया और कई माध्यमों से पता चला कि सभी केंद्र बुक हो चुके हैं , आनन् - फानन में राज्य स्वास्थ्य समिति ने **EYE WASH** के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर 12 परीक्षा केदो पर एक दंडाधिकारी , एक पुलिस पदाधिकारी ,10 लाठी बल और पांच महिला बल की प्रतिनियुक्ति कर दी लेकिन कार्यपालक निदेशक महोदय ने तो परीक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलवा दिया था आजकल परीक्षा ऑनलाइन **NETBOT** ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहे हैं

www.kewalsach.com
निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका
प्रधान कार्यालय
सम्पर्क सख्या
9431073769, 9955077308, 8340360961, 930872
ई-मेल आईडी

पत्रांक :- 07/Kewal Sach/2025 दिनांक :- 17/01/25

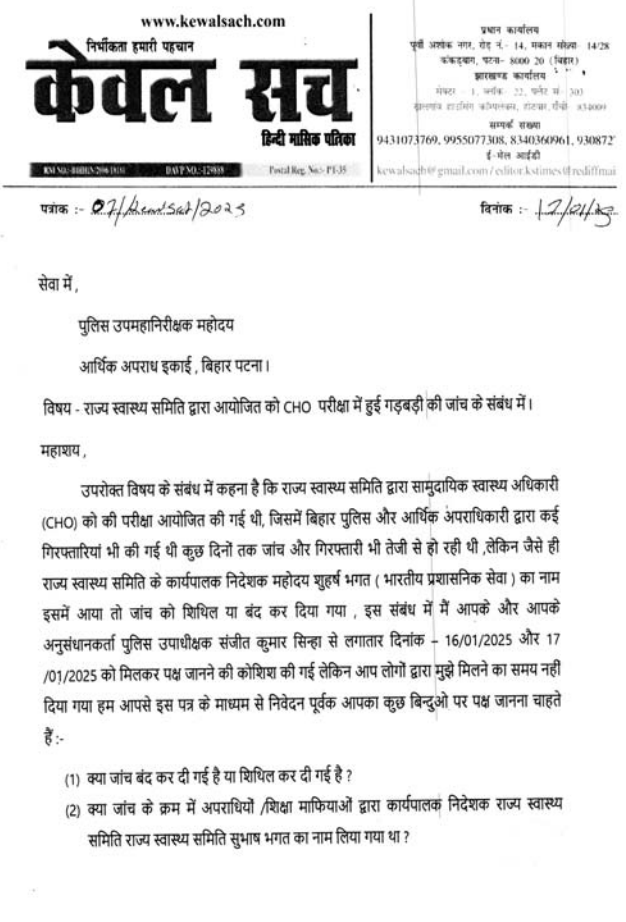

सेवा में ,

पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय
आर्थिक अपराध इकाई , बिहार पटना।

विषय - राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित को CHO परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के संबंध में।

महाशय ,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) को की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार पुलिस और आर्थिक अपराधिकारी द्वारा कई गिरफ्तारियां भी की गई थी कुछ दिनों तक जांच और गिरफ्तारी भी तेजी से हो रही थी ,लेकिन जैसे ही राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक महोदय शुहर्ष भगत (भारतीय प्रशासनिक सेवा) का नाम इसमें आया तो जांच को शिथिल या बंद कर दिया गया , इस संबंध में मैं आपके और आपके अनुसंधानकर्ता पुलिस उपाधीक्षक संजीत कुमार सिन्हा से लगातार दिनांक - 16/01/2025 और 17 /01/2025 को मिलकर पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन आप लोगों द्वारा मुझे मिलने का समय नही दिया गया हम आपसे इस पत्र के माध्यम से निवेदन पूर्वक आपका कुछ बिन्दुओ पर पक्ष जानना चाहते हैं :-

(1) क्या जांच बंद कर दी गई है या शिथिल कर दी गई है ?
(2) क्या जांच के क्रम में अपराधियों /शिक्षा माफियाओं द्वारा कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति सुभाष भगत का नाम लिया गया था ?

3 अक्टूबर, 2024 थी। 22 अक्टूबर 2024 की शाम तक SHSB ने बोलीदाताओं से कोई सम्पर्क नहीं किया। 22 अक्टूबर 2024 की शाम को SHSB से बोलीदाताओं को तीन ई-मेल प्राप्त हुए; पहला मेल बोलीदाताओं को 22/10/2024 को शाम 6:05 बजे प्राप्त हुआ, जिसमें सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियाँ खोलने के लिए आमंत्रित किया गया। 22/10/2024 को ही शाम 06:37 बजे बोलीदाताओं को दूसरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें हमें 23/10/24 को सुबह 11:00 बजे जूम लिंक के साथ SHS द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष ऑफलाइन या वर्चुअल तकनीकी प्रस्तुति देने का निर्देश दिया गया। यह भी कहा जा रहा था कि जो बोलीदाता इस बैठक में भाग नहीं लेगा, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 22/10/2024 को शाम 06:55 बजे बोलीदाताओं को तीसरा मेल मिला, उसमें कहा गया था कि कवर-1 का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और आप पात्र हैं। इसका मतलब है कि सभी प्रतिभागियों को आमंत्रण भेजे जाने से पहले तकनीकी विश्लेषण प्रक्रियाएँ पूरी नहीं की गई, जबकि वित्तीय उद्घोषणा के लिए अंतिम योग्य बोलीदाताओं की घोषणा 23/10/24 को निर्धारित तकनीकी प्रस्तुति सत्र के बाद की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि यह पहले से ही तय था कि तकनीकी योग्यता मायने नहीं रखती या मामला सेट हो गया है? इससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठता हैं। तकनीकी प्रस्तुति कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2024 को निर्धारित था और वित्तीय बोलियाँ उसी दिन शाम 4:00 बजे खोली गई। दोनों कार्यक्रमों के बीच एक घंटे का अंतराल प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। निविदा खंड 2.4 (धारा-V, पृष्ठ-27)-ग्राहक (सरकारी/निजी) द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, साथ में कार्य आदेश/एमओयू/अनुबंध/समझौता, जिसमें पिछले 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान प्रति वर्ष किए गए पैथोलॉजी परीक्षणों की संख्या का प्रमाण हो। हालांकि, यह संभव है कि कुछ बोलीदाताओं, जैसे हिंदुस्तान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और जेआईटीएम स्किल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास यह प्रमाण पत्र न हो। इसके बावजूद, उन्हें योग्य माना गया और वित्तीय उद्घोषणा के लिए आमंत्रित किया गया। वित्तीय बोलियों के खुलने के बाद, साइंस हाउस 77.06% की अधिकतम छूट के साथ L1 था, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले में L2, L3... को NIT (बिंदु 8.3, पृष्ठ-10) में उल्लिखित नियम के अनुसार L1 मूल्य पर काम करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन यहां अन्य प्रतिभागियों को आमंत्रित किए बिना ही हिंदुस्तान वेलनेस को 77.06% के स्थान पर 73.05% की दर पर एलओआई जारी कर दिया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक बिल पर सरकारी धन की 4% हानि को दर्शाता है। इस बिंदु का पालन क्यों नहीं किया गया? मांगी गई परफॉरमेंस सिक्योरिटी के अनुसार, जो कि 1000000.00 (दस करोड़) रुपये है, ऐसा माना जाता है कि टेंडर का मूल्य लगभग 800 करोड़ रुपये है। ऐसी स्थिति में 4 प्रतिशत की छूट बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं: - लगभग 60 पूर्ण स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का क्या होगा, जिनमें अधिकांश उपकरण पिछले तीन वर्षों में लगाए गए हैं और वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं? बिहार के विभिन्न डीएच/सीएचसी/पीएचसी आदि में लगाए गए लगभग 1200 अर्ध-स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का क्या होगा? विभिन्न अस्पतालों में लगाए गए 1000 से अधिक 3-भाग सीबीसी उपकरणों का क्या होगा? एलिसा रीडर और वॉशर, कोएगुलेशन एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर आदि जैसे सैकड़ों पहले से स्थापित उपकरणों का क्या होगा? नए टेंडर के अनुसार नए बोलीदाता को सभी सुविधाओं में नए उपकरण लगाने होंगे, मैनपावर, एलआईएमएस और बहुत कुछ उपलब्ध कराना होगा। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पहले से काम कर रहे लैब तकनीशियनों का क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में स्थापित सभी उपकरणों की कार्यक्षमता बनाए रखने और सेवा प्रदान करने के लिए केटीपीएल के साथ सेवा अनुबंध (बीएमएमपी परियोजना के तहत) का क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार सरकार लगभग 3000 नए लैब तकनीशियनों की नियुक्ति करने जा रही है। इस टेंडर के बाद ऐसी जरूरतें खत्म हो जाएंगी।

पैथोलॉजी मूल्यांकन के सभी नियम कार्यों को सुहर्ष भगत ने अपने जेब में रखकर हिंदुस्तान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को बिना उचित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के ही तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया। हुआ यह कि BID के नियमों के अनुसार बोलीदाताओं को 20 लाख टेस्ट का प्रमाण पत्र किसी निजी या सरकारी संस्थानों से लेकर देना था, लेकिन सूत्रों के अनुसार सुहर्ष भगत ने मात्र 20 लाख रुपए लेकर हिंदुस्तान वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर एकाउंटेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को ही संस्थाओं का प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार कर उसे तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया और उसे L2 रेट पर ही L1 घोषित कर उसके साथ इकरारनामा कर लिया।

केवल सच, सुहर्ष भगत की काली दुनियां तक अपनी पहुंच बना चूका हैं। कुछ सबूत के इंतजार में हम उनकी संपत्ति के बारे में आपको इस अंक में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप भरोसा रखें सबूत जल्द केवल सच के पास होगा और काली दुनिया का काला धन का भी खुलासा केवल सच में होगा।●

राजनीतिक पहुंच के कारण NMC नियमों का उल्लंघन कर बने हैं अधीक्षक

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, राज्य विधान मंडल अधिनियम (सरकार) के तहत एक संस्थान, 19 नवंबर 1983 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह बिहार राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में से एक है। यह बिहार सरकार का एकमात्र सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान है। संस्थान चिकित्सा में शिक्षा प्रदान करता है और बिहार में कई स्वास्थ्य और औषधीय अनुसंधान करता है। इसे सितंबर 2011 में MCI (अब NMC) से मेडिकल कॉलेज की संबद्धता प्राप्त हुई। इसमें 120 मान्यता प्राप्त MBBS सीटें हैं। इसे MBBS, MD, MS, M.Ch, DM, DNB, Ph. D.और विभिन्न पैरामेडिकल डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस), पटना और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, लखनऊ की स्थापना एक ही समय हुई थी, लेकिन एसजीपीजीआई लखनऊ अपने उच्चत्तम शिखर को छू रहा है और आईजीआईएमएस की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। शुरू से ही यह संस्थान जातिवादी मानसिकता का शिकार रहा है। भाई-भतीजाबाद इस पर हावी रहा है। एसजीपीजीआई और आईजीआईएमएस दोनों के ही पहले निदेशक डॉक्टर टंडन थे।

आज आप आईजीआईएमएस चल जाइए, आपको इमरजेंसी में एडमिट करने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद भी आपका मरिज अगर किसी प्रकार भर्ती हो भी जाता है तो जाँच के लिए लंबी लाईन, उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबी लाईन लगानी पड़ती है। मरीज को बेड रहते हुए भी बेड नहीं कह कर भर्ती नहीं लिया जाता है। आईजीआईएमएस के इस दुर्दशा का एकमात्र जिम्मेदार वर्तमान में कार्यकारी अधीक्षक डॉ० मनीष मंडल हैं।

आईजीआईएमएस पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान है, लेकिन यहां के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ना तो MCH है और ना तो DNB। उनके राजनीतिक और न्यायिक प्रभाव के कारण इन्हें आईजीआईएमएस का सांस्कृतिक विभाग का सचिव, स्पोर्ट्स विभाग का सचिव, एथिक्स कमेटी का सचिव, सर्जरी का विभाग अध्यक्ष, SOTTO का अध्यक्ष, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हेड और अधीक्षक आईजीआईएमएस बना दिया गया है। मनीष मंडल का कद और उनकी पहुंच का अनुमान आपको इस बात से चल जाएगा कि डॉक्टर मनीष मंडल 2001 से 2005 तक

आईजीआईएमएस में सीनियर रेजिडेंस के रूप में रहे और 2007 में ही इनके वरीय डॉक्टर को संस्थान में रहते हुए इन्हें उपाधीक्षक बना दिया गया। 2014 में इन्हें एडिशनल अधीक्षक आईजीआईएमएस बना दिया गया। 2017 में डॉक्टर पी.के. शाही के सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष आईजीआईएमएस बना दिया गया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को 10 सालों का प्रशासनिक अनुभव होना जरूरी है साथ ही यह पद अस्थाई व्यवस्था के तहत होना चाहिए ना की कार्यकारी व्यवस्था के तहत। चूँकि डॉक्टर मनीष मंडल 2007 से 2008 तक उपाधीक्षक और 2014 से 17 तक अतिरिक्त अधीक्षक के रूप में रहे तो, इनका कुल प्रशासनिक अनुभव मात्र 4 साल ही था, इसलिए इन्हें वरीय डॉक्टर के रहते हुए भी कार्यकारी अधीक्षक आईजीआईएमएस उनके राजनीतिक पहुंच और न्यायिक व्यवस्था में पहुंच के कारण बना दिया गया।

आज आईजीआईएमएस में होने वाले विकास कार्यों में डॉक्टर मनीष मंडल को संवेदकों को कमीशन देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी को गलत तरीके से फंसा कर काली सूची में डाल दिया जाता है। इनके द्वारा एक कंपनी को किस तरह से काली सूची में दर्ज करवाया गया और फिर उसे कितना रुपया लेकर उसे काली सूची से हटाया गया, इसका वर्णन हम अपने अगले अंक में करेंगे।

राज्य सरकार ने कई करोड़ रुपए खर्च कर आईजीआईएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भारी-भरकम सेटअप तैयार किया है। दूसरे राज्यों में डॉक्टरों को भेज कर उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया गया। आज इतने सालों बाद भी मात्र एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, वह भी असफल साबित हो गया। तब से लेकर आज तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट बंद है।

डॉक्टर मनीष मंडल के दबाव में इमरजेंसी में रात में कोई भी रोगी एडमिट नहीं लिया जाता है क्योंकि मनीष मंडल के बदौलत कई निजी अस्पताल चलते हैं। आईजीआईएमएस के इमरजेंसी के सामने आपको कई निजी एंबुलेंस मिल जाएंगे, जो निजी अस्पताल के हैं। आपका रोगी अगर इमरजेंसी में आया और भर्ती नहीं हो रहा है तो कई आदमी आपके भाषा को पकड़ कर आपका रिश्तेदार बनकर आ जाएगा और आपके निजी अस्पताल में पहुंचा देगा। यह रिश्तेदार निजी अस्पताल के दलाल और मनीष मंडल के स्टाफ हैं। आईजीआईएमएस से एक रोगी निजी अस्पताल में भेजा जाता है तो मनीष मंडल को 30000/- रेफरल यानी दलाली मिलता है। डॉक्टर मंडल का आईजीआईएमएस में सारे परचेज कमेटी में अपना प्रभाव है, जिसके कारण यह जिसको चाहते हैं उन्हीं को क्रय आदेश मिलता

है।

आईजीआईएमएस कैंपस में छात्रा से छेड़खानी के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स बवाल पर उतर आए थे। छात्रों का बवाल 2 दिनों से चल रहा था। छात्रों का कहना है कि अधीक्षक मनीष मंडल से मामले की शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे नसीहत दे डाली कि छात्राएं देर रात बाहर न घूमें। अधीक्षक का कहना था कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना प्रबंधन के बस में नहीं है। कॉलेज प्रबंधन के इस ढ़ीले रवैये से छात्र बौखला गए और प्रदर्शन पर बैठ गए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के भारी विरोध के बाद आईजीआईएमएस निदेशक एन. आर. विश्वास ने अधीक्षक मनीष मंडल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। लेकिन निदेशक महोदय को 4 दिन में ही इन्हें अधीक्षक के पद पर पुनः बहाल करना पड़ा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी पार्टी ने इनपर काफी दबाव बना दिया था और इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी थी।

डॉक्टर मनीष मंडल के कारण आज आईजीआईएमएस जो एसएसजीपीजीआई के साथ खुला था, आज बद् से बद्तर स्थिति में आ गई है। बिहार सरकार ने आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों को मुफ्त दवा देने का आदेश जारी किया, लेकिन मनीष मंडल को तो दवा दुकानों से कमीशन ही बंद हो जाता। तब इन्होंने इसको इतना पेचीदा बना दिया की दवा की उपलब्धता ही मुफ्त में नहीं हो पा रही है। यह दवा खरीद करने वाली संस्थान बीएमएसआईसीएल को अधियाचना या तो तो कम से कम भेजते हैं, नहीं तो जो दवा सूची में नहीं है उसी की अधियाचना भेजते हैं। आईजीआईएमएस के डॉक्टर भी इनसे खौफ खाते हैं। इनके खौफ से परचेज कमेटी इन्हीं का हुक्म मानती है। डॉक्टर मनीष मंडल आईजीआईएमएस के परिसर और बाहर अपराधी तत्वों के लोगों को पनाह देकर रखते हैं ताकि उनका इस्तेमाल किसी की कलम बंद करने के लिए किया जा सके।

IMS Patna - OPD Room Wise Queue Management

Time: 11:58:45 AM

Department Name	Room Name/ No.	Time Slot	Token Range	Average Time	Total Registered Patients
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	005	11:30-12:30	37-48	5 Min	47
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	008	11:30-12:30	No Patient Pending	5 Min	37
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	009	11:30-12:30	37-48	5 Min	47
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	010	11:30-12:30	37-48	5 Min	42
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	011	11:30-12:30	37-48	5 Min	38
Regional Institute Of Ophthalmology Rio	----	11:30-12:30	37-48	5 Min	47
Reproductive Medicine	RM 1	11:30-12:30	No Patient Pending	5 Min	20

IMS Patna - OPD ise Queue Management

Time: 12:02:16 PM

Department Name	Room Name/ No.	Time Slot	Token Range	Average Time	Total Registered Patients
Orthopaedics	Room 6 Room 7	11:30-12:30	37-48	5 Min	130
Otorhinolaryngology Ent	Room 32	11:30-12:30	37-48	5 Min	201
ain And Palliative Care	Room 114	11:30-12:30	No Patient Pending	5 Min	3
Pediatrics	GP 1	11:30-12:30	37-48	5 Min	56
Pediatric Surgery	Room 4	11:30-12:30	No Patient Pending	5 Min	20
Physical Medicine And Rehabilitation PMR	PMR 1	11:30-12:30	37-48	5 Min	44
Physiotheraphy	Room 105	11:30-12:30	No Patient Pending	5 Min	6

इमरजेंसी सेवा के आगे बोर्ड, जिसमें मरीज की संख्या और बेड की उपलब्धता का विवरण होता है, जान बूझकर इनके द्वारा खराब कर दिया गया, ताकि बेड रहने के बावजूद भी रोगियों को भर्ती ना किया जा सके और उन्हें निजी अस्पतालों में भेजा जा सके।

इमरजेंसी सेवा के सामने रोगियों के परिजन के लिए एक आश्रय है, जिस पर सेड डाला हुआ है, लेकिन इस ठंड के मौसम में भी वह खुला है। जिससे रोगियों के परिजन ही रोगी बन जा रहे हैं। आईजीआईएमएस की दुर्दशा से ना तो सत्ता पक्ष को मतलब है ना ही विपक्ष को, क्योंकि मनीष मंडल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं की सुनते हैं और उनके कहने पर मरीज को भर्ती कर लेते हैं। विपक्ष के बड़े नेता का हाथ मनीष मंडल पर है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का साथ भी मनीष मंडल को है। माननीय मंत्री आजकल वसूली मंत्री से उद्घाटन मंत्री हो गए हैं। उद्घाटन करने आईजीआईएमएस तो आते हैं, लेकिन आईजीआईएमएस की दुर्दशा पर इनका ध्यान नहीं जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का बेड़ा गर्क कर अब बिहार बीजेपी का बोरिया-बिस्तर समटवाने में लगे हुए हैं।●

बिहार विधानसभा में आयोजित हुआ 85वाँ अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन

☞ **कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की कही बात**

☞ **पांच संकल्पों के साथ हुआ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन**

● **अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

बिहार विधानसभा में दो दिवसीय (20-21 जनवरी 2025) पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। 20 जनवरी को विधान सभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित 85वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का विधिवत् उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कर कमलों द्वारा किया गया। यह सम्मेलन मुख्य रूप से संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान पर विचार-विमर्श को लेकर था। देश के सभी प्रांतों से आये पीठासीन अधिकारियों एवं बिहार विधानसभा के सदस्यों से विधानसभा का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा पड़ा था। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में पहली उपस्थिति बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह एवं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव की हुई। उसके बाद संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री बिहार, श्रवण कुमार ने शिरकत किया। बाद में राज्यसभा के सभापति हरिवंश सिंह के साथ ही राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर रामवचन राय भी सभागार में उपस्थित हुए। हॉल में बैठे सभी आगंतुकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का इंतजार था, तभी उनका आगमन हॉल के भीतर होते ही सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम बिड़ला के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी उपस्थित थे। बता दें कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्जवलित किया गया।

इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम विडला जी को अंग वस्त्र और मेमोन्टो देकर स्वागत किया गया। वही प्रोफेसर रामवचन राय द्वारा श्रवण कुमार को एवं नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अंगवस्त्र एवं मेमोन्टों देकर स्वागत किया गया।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बिहार की गौरवगाथा का परिचय दिया और आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आजादी के पहले और बाद में अब तक का बिहार में यह तीसरा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कराया गया। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इसी विधानसभा में प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन, प्रतिभा देवी पाटिल, रामनाथ काविंद का भी आगमन हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आये थे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया तथा बिहार के पर्यटन में हो रहे विकास पर भी जोर डाला। इसके साथ ही बिहार परिचय को लेकर एक छोटी वीडीयो भी दिखाई गई। अगले वक्ता के रूप में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस सम्मेलन के लिए धन्यवाद दिया। वही राज्यसभा के सभापति

हरिवंश सिंह ने बिहार के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा छात्राओं की साइकिल और पोषाक योजना की शुरूआत को अंतराष्ट्रीय चर्चा का विषय बताया। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बतलाते हुए नीतीश कुमार को बधाई दिया। वही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को बिहार में आयोजन होने का तीसरा मौका बतलाया। उन्होंने बिहार की गौरवगाथा पर चर्चा करते हुए बतलाया कि बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन के साथ-साथ विकास का नया आयाम गढ रहा है। उपमुख्यमंत्री ने बिहार को शिक्षा का केंद्र बताते हुए नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशीला विश्वविद्यालय पर चर्चा की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि 'आप कोटा से हैं और कोटा में सबसे ज्यादा पढ़ने और पढ़ाने वाले बिहार के हैं'। बिहार में टॉप से लेकर बॉटम तक के मजदूर देश के अन्य प्रांतों में हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आईएएस-आईपीएस बिहार से ही होते हैं। साथ ही उन्होंने भाषा पर जोर देते हुए कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में अपनी-अपनी भाषाएं हैं। देश में सभी हिंदी बोलते हैं किंतु बिहार में पांच प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उन्होंने पर्यटन पर चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर बन गया, मां जानकी मंदिर बन रहा है और आगे लव-कुश के मंदिर का भी निर्माण कराने की बात कही। 85वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आये अधिकारियों को उन्होंने सलाह दी की, सदन के अंदर कानून बनाये जाते हैं, उसको गंभीरता से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाये। सभी दल भी बनाये गये कानून का पालन सही से करे इसकी रिपोर्ट त्वरित तैयार करने की जरूरत है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अंत में लोकसभा अध्यक्ष ओम विडला ने अपने भाषण में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर यह सम्मेलन बिहार में किया गया, जिसकी खुशी है। उन्होंने कहा कि जब भी सदन के भीतर किसी मुद्दे या कानून को लाया जाता है तब देखा जाता है कि विरोध में अमर्यादा आ जाती है। सभी दलों को मिलकर इस पर ध्यान देना होगा। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान जरूरी है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

बताते चले कि दो दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 21 जनवरी को देश के विभिन्न

राज्यों से आये पीठासीन अधिकारियों को बिहार के गर्वनर महामहिम आरिफ मोहम्मद खां ने संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने इस सम्मेलन का समापन किया। बता दें कि उक्त अवसर पर राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश, बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव जी और अन्य विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल हुए। सनद् रहे कि 1921 से लेकर आज तक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों को देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने की परंपरा रही है। इन सम्मेलनों में विधायिका की स्वायत्तता, वित्तीय प्रबंधन, समिति प्रणाली, सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार, सदन में अनुशासन और गरिमा, सदन के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बताते चले कि 21 जनवरी के समापन दिवस के उपरांत को पीठसीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी बातों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि पटना में हुए दो दिवसीय इस सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों को ठीक से कार्य करने का संकल्प लेना होगा। आज की इस प्रेस वार्ता में पटना 2025 के संवैधानिक पांच संकल्प को लिया गया है :-

☞ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने भारतीय संविधान निर्माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भारत की जनता और देश के प्रति उनके महान योगदान की सराहना की। यह संविधान, जन भागीदारी पर आधारित शासकीय व्यवस्था का पवित्र दस्तावेज है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य और सामूहिक जन कल्याण की भावनाएं निहित हैं।

☞ संकल्प में भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सामूहिक रूप से भारतीय संविधान के प्रति अपनी संपूर्ण आस्था व्यक्त की तथा संकल्प लिया कि संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप अपने अपने सदनों का कार्य संचालन करेंगे।

☞ भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों ने पुनः सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि विधायी संस्थाओं में बाधारहित व्यवस्थित चर्चा एवं परिचर्चा को सुनिश्चित करेंगे, ताकि विधायी एवं नीतिगत मुद्दों पर जनहित में श्रेष्ठ संवाद का वातावरण बन सके।

☞ भारतीय विधायी संस्थाओं के पीठासीन अधिकारियों ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर इसके मूल्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, शहरी निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक संवैधानिक मूल्यों को योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने का अभियान व कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया, जिससे संवैधानिक मूल्यों की जड़े और गहरी व स्थायी हों और जन सहभागिता पर आधारित यह शासकीय व्यवस्था देश में और सुदृढ़ व मजबूत बने।

☞ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित डिजिटल टेक्नॉलाजी अपनाने की प्रतिबद्धता दोहरायी, जिससे विधायी संस्थाएं भारतवासियों को अत्यंत प्रभावी और श्रेष्ठ रूप से अपनी सेवाएं दे सकें।●

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार , लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब आठ वर्ष के शासनकाल में राज्य की 'तस्वीर' काफी बदल गई है। इस बदलाव का आगाज 2017 से उनके पहली बार सीएम बनने के बाद दिखने लगा था जो आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि पिछले आठ वर्षों में योगी की कार्यशैली और तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। न वह रूके हैं, न थके हैं। लॉ एंड आर्डर, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आज भी उनकी प्राथमिकता में है। बुलडोजर को उनकी दूसरी इनिंग में भी आराम नहीं दिया गया था। यह सब तो प्रशासनिक स्तर पर हो रहा है, वहीं योगी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी वह अपने अंदाज में नया आयाम दे रहे हैं। योगी के पहले कार्यकाल में 2019 में प्रयागराज में शानदार अर्धकुंभ का आयोजन और वाराणसी में बाबा

विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोधार खास रहा तो 05 अगस्त 2020 को उनका प्रधानमंत्री के साथ अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के मंदिर की आधारशिला रखना भी सनातन प्रेमियों के लिये 'मिल का पत्थर' साबित हुआ। इसके करीब सवा साल बाद 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के फेज-1 का उद्घाटन किया तो इस मौके पर भी योगी, पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाये खड़े नजर आये। हिंदू धर्म के लिहाज से देखें तो काशी का ज्योतिर्लिंग 12 में सबसे महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर की नींव खुद पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी।

बात दूसरे कार्यकाल की कि जाये तो यह भी शानदार चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर का उदघाटन करके मोदी के साथ-साथ योगी ने भी करोड़ों सनातन प्रेमियों रामभक्त हिन्दुओं का दिल जीत लिया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही योगी ने प्रदेश के पांच जिलों के मंदिरों के विकास का ऐलान किया है। इसमें लखीमपुर खीरी से उन्नाव हरदोई फर्रुखाबाद जैसे पांच बड़े जिलों के मंदिरों को शामिल किया गया है। इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट घोषित किया गया है, ताकि मथुरा, काशी और अयोध्या जैसा

भव्य स्वरूप इन धार्मिक स्थलों को दिया जा सके। मगर सबसे खास है प्रयागराज में होने जा रहा महाकुंभ-2025,जिसका वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। वैसे तो महाकुंभ मेला-2025 प्रयागराज में 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारियां तीन साल पहले योगी सरकार ने 2022 में दूसरी बार सरकार बनाने के साथ ही शुरू कर दी थी। योगी ने महाकुंभ को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इधर तो शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब योगी ने महाकुंभ के कार्यो की समीक्षा नहीं की होगी। इस कुंभ को योगी की तीन साल की तपस्या का महाकुंभ कहा जाये तो गलत नहीं होगा।महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर हैं।

☞ **योगी ने जारी किया महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह** :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 06 अक्टूबर 2024 को प्रयागराज में महाकुंभ-2025 के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया। महाकुंभ के लोगो का उपयोग महाकुंभ की वेबसाइट और ऐप के साथ अन्य प्रचार माध्यमों में किया जाएगा। वेबसाइट और ऐप श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वायु, रेल और सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचने में काफी कारगर रहने वाला है। इसके माध्यम से प्रयागराज में आवास, स्थानीय परिवहन, पार्किंग, घाटों तक पहुंचने के दिशा-निर्देश आदि की जानकारी मिल सकेगी। इसमें स्थानीय और आसपास के पर्यटन स्थलों की भी जानकारी होगी. मेला स्थल और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी इसके जरिए दी जाएगी।

☞ **महाकुंभ से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा** :- पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने की योगी सरकार की उम्मीदों का आधार इस बार प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ बनता दिख रहा है। पिछले डेढ़ दशक के पन्ने पलटे तो यूपी में सबसे अधिक 58 करोड़ से अधिक पर्यटन 2019 में यूपी में आए थे। इसमें 24 करोड़ से अधिक की हिस्सेदारी लगभग डेढ़ महीने तक चले प्रयागराज कुंभ की थी। इसलिए, 13 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ में लगने वाली आस्था की डुबकी से यूपी की अर्थव्यवस्था को 'अर्थ' के अमृत की आस है। माना जा रहा है कि महाकुंभ में इस बार 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। मानवता की इस सबसे बड़ी जुटान के भरोसे प्रदेश में 2025 में कुल पर्यटन की संख्या 65 से 70 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ

में व्यवस्थागत तैयारियों पर 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। अलग-अलग देशों में भी ब्रांडिंग का असर यह है कि यूरोपीय देश के नागरिक भी महाकुंभ आने या जानकारी हासिल करने के लिये उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं महाकुंभ की आभा पर मां गंगा की कृपा बरसने लगी है। संगम पर गंगा मैइया ने लगभग 300 मीटर स्नान घाट के विस्तार का अवसर दे दिया। ठीक संगम नोज के सामने यह जगह मिल गई है। इससे संगम का स्नान घाट लगभग पांच हजार रनिंग फीट हो जाएगा, जो पहले लगभग साढ़े तीन हजार रनिंग फीट तक ही हो पा रहा था।

☞ **फेक न्यूज रोकने को डिजिटल वारियर्स :-** महाकुंभ में कोई व्यवधान नहीं खड़ा कर पाये इसलिये फेक न्यूज के खिलाफ अभियान चलाने,साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों को इंटरनेट मीडिया के विभिन प्लेटफार्म पर प्रसारित करने के लिए डिजिटल वारियर्स को तैनात किया गया है। इसके लिए युवा पीढ़ी के इंटरनेट मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं कालेज के छात्रों को जोड़ा गया है। वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए एआई से लैस कैमरे लगाए गये हैं। योगी सरकार का कहना है कि प्रयागराज में हर 6 साल पर होने वाले कुम्भ या 12 साल पर होने वाले महाकुम्भ में श्रद्धालुओं की सही संख्या गिनने की अभी तक कोई सटीक तकनीक नहीं थी।

☞ **अस्त्र-शस्त्र संग आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश :-** महाकुंभ का आगाज नजर आने लगा है। सुसज्जित रथों, बग्घियों पर सवार नागाओं, संगम की रेती पर 22 दिसंबर 2025 को श्रीपंच दशनाम आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वरों, श्रीमहंतों, नागा सन्यासियों की छावनी प्रवेश शोभायात्रा निकली तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। विविध रूप वाले बाबाओं को देखने के लिए लोग कतारबद्ध खड़े रहे। रास्ते भर नागा सन्यासियों के दल शस्त्रों, लाठियों से कलाबाजियां भी करते रहे। छतों, बारजों से पुष्पों की वर्षा होती रही। मड़ौका उपरहार से दिन के 12 बजे भगवान सिद्ध गणेश के पूजन के साथ रथों, बग्घियों, सुसज्जित घोड़ों पर सवार होकर आवाहन अखाड़े के संतों की छावनी प्रवेश शोभायात्रा निकली।

☞ **यूनेस्को से कुंभ को मान्यता :-** वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' का दर्जा दिया था। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल में यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आता है और इसे इन चारों जगहों पर बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, हर 6 साल में दो जगहों हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ के बीच में आता है।

☞ **सरकार मीडिया को दे रही महाकुंभ कवरेज की टिप्स** :- मीडिया कवरेज के लिए अंग्रेजी और हिंदी में छपे यूपी सरकार के एक ब्रोशर में पत्रकारों और संपादकों को बताया गया है कि महाकुंभ 2025 को कैसे कवर किया जाए, उन्हें किस तरह की स्टोरी करनी चाहिए और इसके लिए वे किससे बातचीत करें व किसका साक्षात्कार लें. महाकुंभ 2025 की तैयारियां 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ शुरू हुई. तब से मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कई दौरे किए. आयोजन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं तैयारियों का जायजा लिया और कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया. दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की मेजबानी करने के लिए एक अस्थायी शहर, 'महाकुंभ नगर' बसाने के लिए यह जरूरी था. इस नए शहर को बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन-रात खुद को समर्पित कर दिया. जहां स्थायी पुल समय पर नहीं बन पाए, वहां अस्थायी चार लेन वाले स्टील पुल बनाए गए. प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों को चौड़ा किया गया और तीर्थयात्रियों की आमद को ध्यान में रखते हुए उनका सौंदर्यीकरण किया गया. डबल इंजन वाली सरकार ने बेहतर तालमेल के साथ काम किया और यह सुनिश्चित किया कि रेलवे पुल और अन्य बुनियादी ढांचे इस आयोजन की मांगों को पूरा करें।

☞ **जब साक्षी महाराज को कुंभ में नहीं आने दिया गया** :- निर्मल अखाड़ा अपनी नीति-नियम के प्रति सख्त व समर्पित है। पद भले कितना बड़ा हो, लेकिन गलत कार्य करने वाले को क्षमा नहीं किया जाता। यही कारण है कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। साक्षी महाराज निर्मल अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। 10 फरवरी 1997 में भाजपा के चर्चित नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में साक्षी महाराज का नाम जुड़ गया। इस पर अखाड़े ने उन्हें समस्त पदों से हटा दिया। वर्ष 2001 से 2007 तक हुए कुंभ-महाकुंभ में उन्हें शामिल नहीं किया। कोर्ट से बरी होने के बाद पुन: अखाड़े में शामिल किया गया।

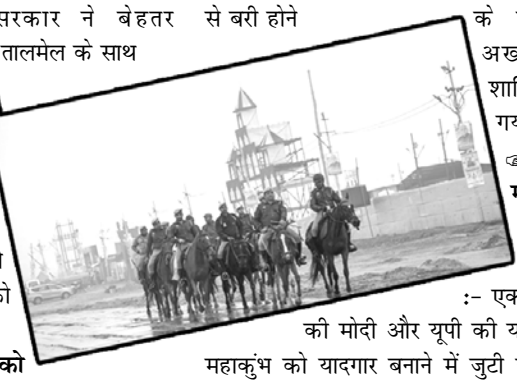

☞ **महाकुंभ पर आतंक का भी साया** :- एक तरफ केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार महाकुंभ को यादगार बनाने में जुटी हैं तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की जमातें चुपचाप पर्दे के पीछे से महाकुंभ में षड्यंत्र का जाल बिछा रहे हैं।खुफिया जानकारी के अनुसार महाकुंभ में अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के लिए सीमा पार से भारत के मीर जाफरों की फौज को सक्रिय कर दिया गया है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में छद्म वेष धारण करके राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी और समाज विरोधी कार्यों को अपने आकाओं के आदेशों पर निरंतर सम्पन्न कर रहे हैं। आतंक के आकाओं की विध्वंसात्मक सरगर्मियों की जानकारी होते ही शासन ने प्रयागराज में सीबीआई टीम गठित कर दी है जो केमिकल अटैक से निपटने में सक्षम बताई जाती है। इसी तरह बम निरोधी दस्तों की संख्याओं में भी इजाफा किया गया है। साइबर अटैक से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं सुनिश्चित की गई है। एनआईए द्वारा विशेष चौकसी बरतने हेतु गुप्त स्थान निर्धारित किये जा चुके है जहां से आयोजन स्थल पर पूरी तरह से निगरानी की जा सकेगी।●

लखनऊ में बांग्लादेशियों की 'सरकार' को चुनौती
देश के लिये बड़ा खतरा

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एशिया की सबसे बड़ी इंदिरा नगर कालोनी के मानस इंक्लेव में 29 दिसंबर को को एक खतरनाक नजारा देखने को मिला, जो भविष्य के लिये बड़ा संकेत समझा जाये तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि यहां ठेला जब्त करने गई नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने लाठी-डंडो से हमला बोल दिया। करीब दो सौ की संख्या में एकजुट भीड़ ने लाठी डंडा लेकर नगर निगम के कर्मियों को दौड़ा लिया और कूड़ा प्रबंधन का काम देख रही मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान की महिला कर्मी मीनाक्षी की न केवल पिटाई की उसके कपड़े तक फाड़ दिये। इसके अलावा एक अन्य सफाई निरीक्षक विजेता द्विवेदी के साथ भी मारपीट की और उनकी कार पर जानलेवा हमला कर किया। इतना ही नहीं उतेजित भीड़ ने अन्य निगम कर्मियों को पीटने के साथ ही इनका मोबाइल और पर्स भी छीन लिया गया।

यह सब करीब एक घंटे तक चलता रहा। यह सब इंदिरा नगर थाने के बगल में बसी बस्ती में हो रहा था। वैसे तो पूरे घटनाक्रम में कोई बहुत खास बात नजर नहीं आती है, क्योंकि अक्सर अतिक्रमण का विरोध करने वाले हमलावर हो जाते हैं, लेकिन यह हमलावर आम हिन्दुस्तानी नहीं थे, बल्कि यह बांग्लादेशी युवक थे, जो अवैध तरीके से सीमा पार करके यहां आकर बस गये थे और जिन्हें कुछ राजनैतिक दलों का समर्थन मिला हुआ था। अवैध तरीके से बसे बाग्लादेशियों को जब हटाया जाने लगा तो यह चिल्लाने लगे कि यह जमीन चांद बाबू की है जो हर झोपड़ी से पांच सौ रूपये किराया लेता है। आश्चर्य तो यह था कि इनको बिजली के कनेक्शन भी बड़ी आसानी से मिल गये थे।

लखनऊ में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों को कई बार आपराधिक वारदात में पकड़ा जाता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादात में एकत्र होकर किसी सरकारी महकमें के कर्मचारियों से इनती बुरी तरह से मारपीट का एक पहला मामला होगा, जो इस बात का भी संकेत है कि समय रहते सरकार नहीं चेती तो यह समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जायेगी। बता दें पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए यूपी मुफीद ठिकाना है। साल दर साल यूपी में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पांच वर्ष पूर्व पुलिस ने प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को चिन्हित करने के

लिए सर्वे किया था। तब पुलिस ने अनुमान जताया था कि प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और करीब 3 हजार रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि केवल लखनऊ में ही करीब एक लाख बांग्लादेशी नागरिकों ने अपना ठिकाना बना लिया है। हालांकि सर्वे के बाद भी इन बंग्लादेशियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अधिकतर मामलों में पाया गया कि स्थानीय नेताओं ने ही उनके भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने में मदद की थी। इनमें से अधिकतर ने असम के निवासी होने का दावा किया था, जिसकी पड़ताल के लिए पुलिस की टीमें भेजी गई थीं। वर्ष 2013 में एडीजी कानून-व्यवस्था रहे प्रशांत कुमार के निर्देश पर रोहिंग्या नागरिकों की धर-पकड़ के लिए कई जिलों में अभियान चलाया जरूर गया था, लेकिन यह किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सका था। यहां बंग्लादेशियों के रायबरेली के सलोन से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र जरूरी है। कुछ माह पूर्व इस घटना का खुलासा हुआ था। यहां करीब 20 हजार फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की कड़ियां बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ी थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि यहां से घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षड्यंत्र चल रहा था। इसके बदले जन सेवा केंद्र (सीएससी) संचालक जीशान खान, सुहेल और रियाज मोटी कमाई कर रहे थे। इसी महीने कर्नाटक पुलिस ने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक संदिग्ध को दबोचा था। उसका जन्म प्रमाणपत्र भी यहीं से बना था। जांच के लिए टीम रायबरेली पहुंची तो धीरे-धीरे पूरा मामला खुलने लगा। पुलिस व प्रशासनिक सूत्रों को तब बताया था कि

सलोन से सर्वाधिक अल्पसंख्यकों के ही फर्जी प्रमाणपत्र बनाए गए हैं। इनमें 2023 में मुंबई में पकड़े गए चार बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले जम्मू में भी पकड़े गए कुछ रोहिंग्या के पास यहां बने जन्म प्रमाणपत्र मिले थे।

बहरहाल, लखनऊ के इंदिरा नगर में बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी के बाद नगर निगम के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस व पीएसी को बुला लिया। कई को मौके से पकड़ा गया। महापौर सुषमा खर्कवाल और विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे गए। इसके बाद निजी जमीन पर बसी बस्ती पर जेसीबी की मदद से उजाड़ दिया गया। कई के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। देखना यह होगा कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। क्योंकि एक तरह से नगर निगम कर्मियों पर हमला करके बांग्लादेशियों ने सरकार को ही चुनौती दे दी है। संभवता इनके मन में खाकी और खादी दोनों का खौफ नहीं रह गया है।●

भागवत को क्यों दी जा रही है धर्म गुरु नहीं बनने की नसीहत

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

अपना देश एक रंग बिरंगे गुलदस्ते की तरह है। अनेकता में एकता जिसकी शक्ति है। यहां विभिन्न धर्म और उनकी अलग-अलग पूजा पद्धति देखने को मिलती है तो देश का सामाजिक और जातीय ताना बाना भी काफी बंटा हुआ हुआ है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पूर्व सौ बार उसके बारे में सोचना पड़ता है।वर्ना देश का माहौल खराब होने या जनता की भावनाएं भड़कने में देरी नहीं लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। वैसे यह भी सच्चाई है कि भागवत के बयान पर पहली बार हो-हल्ला नहीं मच रहा है।इससे पूर्व भी भागवत के आरक्षण, ब्राह्मणों,डीएनए से जुड़े बयानों पर हंगामा खड़ा हो चुका है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर-मस्जिद वाले बयान पर साधु-संतों की ओर से आपत्ति सामने आई है। देश में हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय संत समिति ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हर जगह मंदिर तलाशने और इसके सहारे कुछ लोगों का हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। समिति ने कहा है कि विभिन्न स्थलों पर मंदिर-मस्जिद विवाद को उठाने वाले नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर-मस्जिद का मुद्दा धार्मिक है और इसका फैसला धर्माचार्यों की ओर से किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को छोड़ देना चाहिए।

स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब धर्म का विषय उठेगा तो उसे धर्माचार्य तय करेंगे। जब यह धर्माचार्य तय करेंगे तो उसे संघ भी स्वीकार करेगा और विश्व हिंदू परिषद भी। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि मोहन भागवत की अतीत में इसी तरह की टिप्पणियों के बावजूद 56 नए स्थानों पर मंदिर पाए गए हैं, जो मंदिर-मस्जिद मुद्दों में रुचि और कार्रवाई का संकेत देते हैं। जितेंद्रानंद महाराज ने जोर देकर कहा कि धार्मिक संगठन जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इन समूहों के कार्य उन लोगों की मान्यताओं और भावनाओं से आकार लेते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि केवल राजनीतिक प्रेरणाओं से। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की यह टिप्पणी जगद्गुरु रामभद्राचार्य की ओर से मोहन भागवत से असहमति व्यक्त करने के एक दिन बाद आई है। बता दें जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा था कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासनकर्ता नहीं हैं, बल्कि हम हैं। साधू संत तो भागवत के बयान से नाराज हैं हीं इसके साथ-साथ यह भी पहली बार देखने को मिल रहा है कि आरएसएस प्रमुख को 'परिवार' के भीतर भी विरोध का सामना

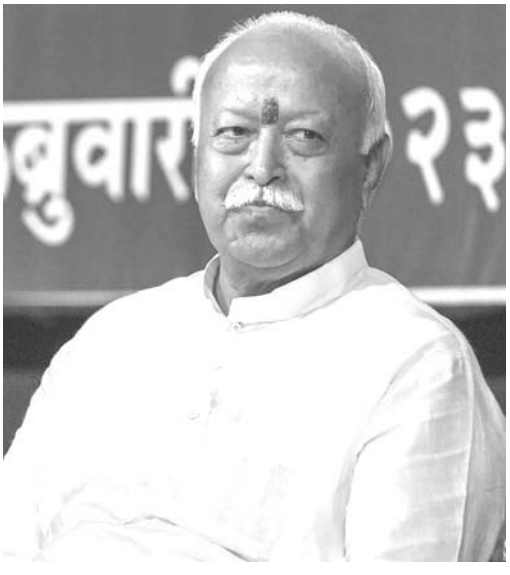

करना पड़ रहा है। इससे पहले द्वारका में द्वारका शारदा पीठम और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती संघ परिवार के खिलाफ रुख अपनाते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित बता कर उनके बयानों को खारिज कर दिया जाता था।

बहरहाल, जगद्गुरु रामभद्राचार्य के साथ-साथ अन्य हिंदू धार्मिक गुरु आरएसएस के सुर में सुर मिलाने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि संघ को आस्था के मामलों में धार्मिक हस्तियों के नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। उधर,राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह स्थिति धार्मिक मामलों में आरएसएस की भूमिका और प्रभाव को लेकर हिंदू धार्मिक समुदाय के भीतर संभावित झगड़े को भी दर्शाती है।रामभद्राचार्य ने कहा कि संभल में जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तव में बुरा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में सकारात्मक पक्ष यह है कि चीजें हिंदुओं के पक्ष में सामने आ रही हैं। हम इसे अदालतों, मतपत्रों और जनता के समर्थन से सुरक्षित करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की।

बता दें हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर-मस्जिद विवादों के फिर से उभरने पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लोगों को ऐसे मुद्दों को न उठाने की सलाह दी। मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर-मस्जिद विवादों को उछाल कर और सांप्रदायिक विभाजन फैलाकर कोई भी हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता। उनका यह बयान हिंदू दक्षिणपंथी समूहों की ओर से देश भर में विभिन्न अदालतों में दशकों पुरानी मस्जिदों पर दावे जैसी मांग के बाद आया है। इस पर हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि ये पुरानी मस्जिदें, मंदिर स्थलों पर बनाई गई थीं। इन मस्जिदों में जौनपुर की अटाला और संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, जिस मामले में हाल ही में हिंसा हुई थी। 24 नवंबर को भड़की हिंसा में पांच लोग मारे गए थे। उधर,आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मंदिर-मस्जिद विवाद न उठाने का बयान लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से था। यह आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है, क्योंकि इसके नेता जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत करते हैं। वे ऐसे मुद्दे उठाने वालों का समर्थन करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरएसएस प्रमुख को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख ईमानदार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए कि भविष्य में संघ ऐसे नेताओं का समर्थन कभी नहीं करेगा जो सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं। जयराम ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मंदिर-मस्जिद का मुद्दा आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। कई मामलों में, जो लोग ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को भड़काते हैं और दंगे करवाते हैं, उनके आरएसएस से संबंध होते हैं।●

● संजय सिन्हा

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अपने शबाब पर है सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को पक्की बता रही है, दिल्ली विधानसभा का गठन सन् 1993 में हुई उसके पहले दिल्ली महानगरीय परिषद् हुआ करती थी, उसके मुखिया यानि मुख्य कार्यकारी पार्षद होते थे जो उस समय विजय कुमार मल्होत्रा हुआ करते थे जो जनसंघ के नेता थे, जब भारत में सभी जगह कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में होते थे उनके नाम के निचे जनसंघ से चीफ मेट्रोपोलिटन काउन्सलर हुआ करते थे, सन् 1993 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली विधानसभा में अपनी जीत पक्की कर सरकार बनाई और पहले मुख्यमंत्री के रूप में मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री बनाये गये, उसके बहुत दिनों बाद साहेब सिंह वर्मा एवं कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज भी दिल्ली मुख्यमंत्री की सपथ लिया था, सन् 1993 में भी बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में सत्ता मिलने के मुख्य अवसर थी जनता दल के रुप में त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला एवं दुनिया में छायी आर्थिक मंदी जो दिल्ली में भी महंगाई कमर तोड़ रही थी, उसके बाद सन् 1998 के चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में बहुमत मिली और श्रीमती शिला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद लगातार दो बार और सन् 2003 एवं 2008 में तीन बार श्रीमती शिला दीक्षित मुख्यमंत्री बनीं एवं 15 वर्षों तक दिल्ली की मूखयमंत्री बनीं रहीं, सन् 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली और एक नई राजनीति दल अन्ना हजारे के द्वारा प्रर्दत अरविन्द केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और 28 सीटों पर चुनाव जीत कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई गई भले सरकार 49 दिनों तक ही क्यों न चली पूनः सन् 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एकतरफा चुनाव जीत इतिहास रचा और 70 सीटों वाली दिल्ली

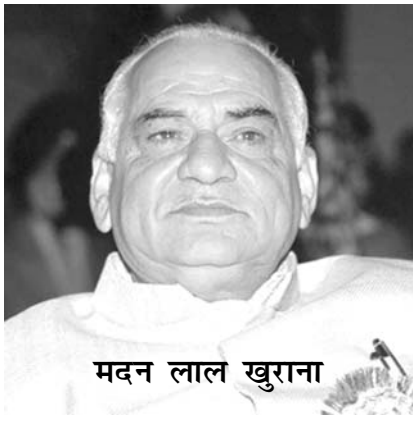
मदन लाल खुराना

शिला दीक्षित

सुषमा स्वराज

अरविंद केजरीवाल

अन्ना का आन्दोलन

विधानसभा में 67 विधानसभा जीत लिया उसके बाद सन् 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी 70 में से 62 सीटों पर चुनाव जीत मजबूत सरकार बनाई, भले आम आदमी पार्टी को पिछले तीन लोकसभा चुनाव सन् 2014, 2019 एवं 2024 में एक भी लोकसभा की सीटें नहीं मिली हो, परंतु दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट किया आम आदमी पार्टी को इसे मुफ्त के बदले मिली हुई ईनाम भी कहा जा सकता है, इस बार की दिल्ली विधानसभा चुनाव थोड़ी कठिन जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए क्योंकि बाकी दोनों राजनीति दल भाजपा और कांग्रेस के लिए तो चुनाव कठिन ही रहा है? दिल्ली में कुल चार तरह के मतदाता हैं माने जाते हैं, सबसे पहले मुस्लिम समुदाय दूसरे मध्यम वर्गीय परिवार तीसरे झुग्गियों के परिवार एवं चौथे उच्च वर्ग परिवार, तो सबसे पहले उच्च वर्ग परिवार के 20ः प्रतिशत भी चुनाव में वोटिंग नहीं करते वो चुनाव के दिन या तो आराम करते या कही घुमने निकल जातें हैं, इस वोट को आप भाजपा के वोट मान सकते हैं, दूसरे वर्ग जो कि मध्यम वर्गीय परिवार जिसके अधिक वोट पिछले तीन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलती रही है जो कभी भाजपा के वोटर हुआ करते थे, इसबार मध्य वर्गीय परिवार केजरीवाल से अलग हो रही है ऐसा बताया जा रहा है, बातें करें कि पहले नंबर के मतदाताओं के तो वो मुस्लिम मतदाता हैं जो अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आगे कौन लग रही है या ऐसा कहें कि हिन्दू वोटर इन दोनों पार्टियों में किसे वोट करती है? इन दोनों में हिन्दू वोट जिसे ज्यादा मिलेगी उसे ही मुस्लिम मतदाता मतदान करेगें, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम कांग्रेस को वोट करना चाहती है, इसके कई कारण हो सकतें है? उसके सबसे बड़े कारण है कि कांग्रेस कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकती और उदाहरण के लिए इतिहास को देखा जाये तो? मुस्लिम मतदाताओं को भारत में विशेष सुविधा शुरू से कांग्रेस पार्टी ही दिया है, वो वक्फ बोर्ड हो या हज सब्सिडी, वेसिप एक्ट, अल्पसंख्यक दर्जा, हज हाउस, मदरसा संचालन वगैरह, इस अधार पर कांग्रेस मुस्लिमो की पहली पसंद बन जाती सम्पूर्ण भारत में मुस्लिमो को अलग अलग राज्यों में वहाँ क्षेत्रीय दलों को वोट करना मजबुरी है वरना पहली पसंद तो कांग्रेस पार्टी ही है, इस बार दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलना बड़ी मुश्किल है, परंतु दिल्ली की महिलाओं को 21 सौ रूपये की प्रलोभन बहुत बड़ी कारण बन रही है आम आदमी पार्टी को चौथी बार सत्ता में आने के लिए, बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी के 21 सौ रूपये वाली शुंगफा का हवा नहीं निकाल देती चुनाव से बहुत पहले तो ये बहुत मंहगा पड़ेगा एवं कारण बनेगा दिल्ली विधानसभा में नहीं आने की? बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मतदाता को नहीं समझा पा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में एक हजार रुपये भी वादा करके नहीं दे पा रही है, दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम एवं बंगलादेशी समस्या, मुफ्त की अलोकतांत्रिक राजनीति देश और राज्य को बर्बाद नास कर देगी वगैरह, बीजेपी के अंदरूनी खीच-तान अभी सबसे ज्यादा है वापस में किसी अन्य दलों के मुकाबले, बीजेपी के कार्यकर्ता 90 प्रतिशत सिर्फ मोदी सरकार के नाम पर एवं भारत माता की जय के सहारे दिल्ली विधानसभा जितना चाहती है, चुनाव अभी एकावन उन्चास के बीच में चल रही है। अगर कांग्रेस अपने दबंग उम्मीदवार और मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है और मुसलमानों के बड़बोले नेता असबुद्दीन ओबैसी दिल्ली के कमसेकम दो दर्जन सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी के लिए थोड़ी आसान

दिल्ली विधानसभा हो सकती है? कांग्रेस द्वारा बनाई गई इन्डी ऐलाइन्स के अभी भी आम आदमी पार्टी है और ये दोनों दल एक दूसरे को चोर बता रहीं हैं.

☞ **केजरीवाल के लिए जीवन मरन :-** ऐसे तो राजनीति आम जनता के लिए तौबा कि बातें हैं, फिर भी समाज के लोगों अपना मतदान कर जिम्मेदारी पूर्ण मानती है, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे ईमानदार पार्टी की छवि लेकर राजनीति में आने को कहा था एवं पुर्ण बहुमत की सरकार बनने पर लोकपाल बनाने की बातें कह कर 2020 में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीते फिर भी लोकपाल बनाने की कभी चर्चा तक नहीं करती कोई बात नहीं? परंतु दिल्ली सरकार करोना काल में दिल्ली को बिल्कुल केन्द्र के सहारे छोड़ कर केजरीवाल के पुरी केबिनेट कोरोनटाईन हो गई थी, सम्पूर्ण दिल्ली अस्त व्यस्त रही थी न अस्पताल में सुविधा थी और न आक्सिजन, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली में करोना सबसे ज्यादा हुई थी और मौतें भी किसी भी अन्य राज्यों के मुकाबले, दिल्ली में कोरोना

दिल्ली में पूर्वांचलियों को छला गया : संतोष ओझा

दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष ओझा बताते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचलियों को सन् 1998 के चुनाव के बाद से ही छला गया है पूर्वांचल के लोगों ने कांग्रेस सरकार और आम आदमी पार्टी के सरकार को पिछले 27 वर्षों से देख रही है और अब तंग है अपनी सुविधाओं के लिए, पूर्वांचलियों के दुखों का उनहोंने चर्चा करते हुए बताया कि बहुत कम पूर्वांचलियों के अपने घर है, इसलिए ऐसे लोगों को बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है, अगर किसी को कुछ लाभ है भी तो किरायेदारों को कोई मुफ्त कुछ भी नहीं है, छोटे बस्तीयों में पानी सीवर की स्थिति नरकीय अवस्था में है किसी के नये राशन कार्ड पिछले 10 वर्षों में नहीं बनाई गई है, करोना काल में मुस्लिमों को तो राशन फ्री की जरुर मिली परंतु किसी पूर्वांचलियों या अन्य हिन्दूओं बस्ती में नहीं मिली श्री संतोष ओझा ने बताया कि पिछले दो वर्षों से पूर्वांचलियों की रूझान 90 प्रतिशत भाजपा के तरफ है जो चुनाव के दिन 5 फरवरी को 100 भी हो जाये तो आश्चर्य नही होने चाहिए? अब पूर्वांचलियों सहित किसी भी जनता के साथ भेदभाव नही किया जायेगा। भाजपा सरकार में जैसा कि केजरीवाल और मार्लेना सरकार में किया जाता रहा है, संतोष ओझा ने बंगलादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को बसाने और विशेष सुविधा केजरीवाल सरकार के द्वारा देने की बातें बताई।

दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ हुआ खिलवाड़ : रविन्द्र गुप्ता

दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रदेश महामंत्री व मेयर रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस बार दिल्ली की आम जनता से लेकर गरीब जनता तक अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाला काम एवं घोटाले को देख चुकी है, गरीबों के बच्चों को एक बोतल शराब के बदले एक फ्री देकर जहर का काम किया है और वैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आम आदमी पार्टी पंजाब में एक हजार रुपये महिलाओं को देने की वादा कर के भाग रही है, दिल्ली की जनता सब जानती है कि पंजाब में सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है इसलिए हमारी दिल्ली की माता बहन बेटी अब अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है, केजरीवाल ने लोकपाल का नाम अब नहीं लेते, अब लेगें भी कैसे? ये भष्ट्राचारी ढ़ोंगी झूठे जो ठहरे , रविन्द्र गुप्ता से जब पुछा कि बीजेपी में वापसी मतभेद बहुत है तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है बीजेपी में पूरी एकजुटता है हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एक सीपाही है और हमसब राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय नैतृत्व के आदेशों का पालन करते हैं, मौका किसी को भी मिले हम सभी सीपाही एक होकर कामों में लग जातें हैं, हमारे नैतृत्व कभी निर्णय गलत नहीं करता, अभी भाजपा के सिर्फ 29 सीटों के नामों की घोषणा हुई है अभी 41 सीटों की घोषणा नहीं हुई है जिसमें हमारे सदर बाजार विधानसभा भी है, अंत में रविन्द्र गुप्ता ने दिल्ली वालों के लिए ये घोषणा किया कि ष्अबकी बार जनता अपने लिए सिर्फ वोट नहीं कर? अपने बच्चो के भविष्य के लिए भी वोट करें और इस बेवफा शराब प्रोत्साहन केजरीवाल को सत्ता से दूर भगाये।

अभी पुर्ण रुप से समाप्त भी नहीं हुई थी कि केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्कीम लेकर आ गयी और उन्होंने एक बोतल खरीद पर एक बोतल फ्री देना शुरू कर दिया और शराब के ठेके को बढ़ा कर दोगुना कर दिया, उस शराब नीति में दिल्ली सरकार को रैवन्यू अप्रत्यक्ष रूप से माफियाओं एवं दलालों को ट्रांसफर कर दिया और उसके बदले माफियाओं ने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को आर्थिक मदद किया गया था जिसकी जांच में अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, अभी हाल तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन्डी एलाईन्स के साथ थी और अभी भी लिखित रूप में अलग नहीं हुई है, जिसने 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सात सीटों में से चार पर चुनाव लड़ा एवं तीन सीटें कांग्रेस को दे दिया, केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए तीन सीटें छोड़ा ही नहीं बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया जीत पक्की होने के लिए कसमें भी खाई और आज वे कांग्रेस को खराब बता रही है, इसीलिए तो आम जनता राजनीति एवं राजनीति दलों में गंदगी मानती है इन्हीं सब कारण से अरविंद केजरीवाल पर लोगों का विसवास आई थी और अन्ना हजारे आदोलन में आम जनता युवाओं की एक फौज खड़ी हो गई थी जो अब पूरे तरीके से उनकी फ्री योजनाओं पर आधारित है,अरविंद केजरीवाल ने चुनाव रेबड़ीयां जैसे शब्द को बोलकर खुली खुली दिल्ली की जनता को बेज्जती कर दिया और बताने की प्रयास किया है कि आप जनता मुफ्त फ्री की जाल में ही फस सकते हो, लो मैं और फ्री योजना ला रहा हूँ, परंतु पहले चुनाव जिताओं फिर मुफ्त में रेबड़ीयां मिलेगी? जबकि पंजाब की जनता को अभी तक एक हजार रुपये नहीं मिले हैं, दिल्ली में बिजली पानी की फ्री योजना में पुरी तरीके से दीमक लग चुकी है बिजली सब्सिडी की वजह से बिजली कंपनियों की बकाया भी एक नई घोटाले सामने आयेगी दिल्ली सरकार की फ्री योजनाओं में दिल्ली जल बोर्ड में पहले से घोटाले की जिन्न निकल चुकी है, डीटीसी की बसें शिला दीक्षित के समय से एक चौथाई लगभग 2 हजार बसे दिल्ली में बची हुई है, वैसे तो दिल्ली सरकार की मुहल्ला किल्लिनिक जो इन्होंने खुद को शुरुआत किया था उसकी संख्या भी चालू स्थित में एक चौथाई ही बचें है, जबकि दिल्ली में महानगरीय परिषद् के जमाने की हेल्थ सेंटर,पोली किर्ल्लिनक की स्थिति बदतर है या बंद हो गई है, इन सबके बाद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी से फिलहाल आगे लग रही है? कारण मुफ्त की मृगमरिचिका ही क्यों न हो? अरविंद केजरीवाल के लिए अबकी बार दिल्ली विध ानसभा चुनाव जीवन मरन की स्थिति वाली है.

☞ **प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव का बिगुल फूंका** :- दिल्ली चुनाव तिथि की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित जे जे कालोनी के लोगों के लिए स्वाभिमान अपार्टमेन्ट की उद्घाटन किया और 1675 नव निमित्त फ्लैटों को डीडीए दूरा दूसरी सफल इन- सिटू स्लम पुनर्वास परियोजना हैद्य इस फ्लैट में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस है, जो फ्लैट दूर से ही सुंदर लग रहें हैं, प्रधानमंत्री ने नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनीनगर में जीपीआरए टाईप- टू क्वार्टर का भी उद्घाटन किया, इस अवसर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चुनावी शंखनाद कर दिया और आम आदमी पार्टी सरकार के नाम लिये बिना आपदा को दिल्ली से हटाना है और भाजपा को लाना है के नारे लगाये, दस साल दिल्ली को बर्बाद करने की बातें कही दिल्ली की विकास ठप्प करने किया जैसे संवाद से लोगों ने तालियां तो जरूर बजाई परंतु अधिकतर लोगों ने केजरीवाल के लिए फ्री योजना का लालच लिया हुआ था। ●

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद

का पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया तक का सफर

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद का जन्म 15 जुलाई 1949 को बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ। जस्टिस सी.के. प्रसाद की स्कूली शिक्षा पटना हाईस्कूल से हुआ है। इन्होंने विज्ञान और कानून में मगध विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। 27 नवम्बर 1973 को अधिवक्ता के रूप में वह नामांकित हुए। माननीय न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। वह जब कभी भी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय को देखते थे तब उनके मन में आता था कि काश मैं न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठा होता तो समाज के लोगों को न्याय दिला पाता। वह सिविल, संवैधानिक, आपराधिक और सेवा मामलों के काफी अच्छे जानकार थे। इन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, आपराधिक और सेवा मामलों में वकालत किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री चन्द्रमौली कुमार प्रसाद अधिवक्ता के रूप में भी पटना उच्च न्यायालय में काफी प्रसिद्ध हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 14 जुलाई 1989 को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। जस्टिस सी.के. प्रसाद बिहार सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में 14 दिसम्बर 1993 को नियुक्त हुए। पटना हाईकोर्ट के स्थायी न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने 08 नवम्बर 1994 को पदभार ग्रहण किया। 21 नवम्बर 1994 को न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद का स्थानांतरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर दिया गया। 10 सितम्बर 2001 को पुन: इनका स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में कर दिया गया। लगभग सात वर्षों तक पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति की सेवा देने के बाद इन्हें पटना हाईकोर्ट में कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। माननीय न्यान्यमूर्ति सी. के. प्रसाद पटना उच्च न्यायालय में 03 मार्च 2008 से 12 मई 2008 और 17 दिसम्बर 2008 से 15 मार्च 2009 तक कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किए। इन्होंने अपने कार्यकाल में पटना हाईकोर्ट में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती कराया। विभिन्न पदों पर बहाली से मुवक्किल और वकीलों को काफी राहत मिला। कर्मचारियों की कमी दूर हुई और पटना हाईकोर्ट में न्याय व्यवस्था माननीय न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद के कार्यकाल में काफी सुदृढ हुआ। उन्होंने ससमय सरकार को भी अपने फैसले से फटकार लगाया और भारतीय दंड संहिता में 498A का भी जबरदस्त दुरुपयोग पर दिशा-निर्देश दिए। उनका बहुत सारे फैसलों का मिशाल आज भी दिया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मार्च 2009 को शपथ लिए। इन्होंने 8 फरवरी 2010 से 14 जुलाई 2014 तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। 25 नवम्बर 2014 में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने थे। भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने के लिए ससमय सुधार और इसके स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1966 में संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। यह परिषद प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत कार्य करती है। चर्चित न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद को केन्द्र सरकार ने 23 मई 2018 को उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।

माननीय न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वरीय अधिवक्ता हैं। बड़ा पुत्र अरदेंदुमौलि कुमार प्रसाद नेशनल ग्रीन ट्रिबूजल में स्थायी वकील भी रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा भी दे चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। वह राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। माननीय न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद की बड़ी बहू भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रसिद्ध वकील हैं। इनके छोटे पुत्र भारतीय सेना में बड़ा ऑफिसर हैं और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में इनका योगदान काफी सराहनीय एवं प्रशंसनीय रहा है। माननीय न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद की पत्नी पटना के कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। जस्टिस सी.के. प्रसाद पटना गोल्फ क्लब के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह अक्सर गोल्फ खेलने पटना गोल्फ क्लब में जाया करते थे। माननीय यायमूर्ति सी. के. प्रसाद कॉमनवेल्थ के अंग्रेजी भाषी संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जस्टिस सी.के. प्रसाद जहाँ भी रहे, वहाँ अपना एक अमिट छाप छोड़ दिए हैं। वह कई बेहतरीन और ऐतिहासिक के फैसलों के लिए याद किए जाने वाले जज हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के लोगों की सेवा में लगाया है।●

जस्टिस प्रेमशंकर सहाय के जन्म शताब्दी समारोह पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

कई बेहतरीन और ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किए जाने वाले पटना हाई कोर्ट के जाने माने जज जस्टिस प्रेमशंकर सहाय के 100वें जन्मदिन पर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन राजधानी पटना में किया गया। इस आयोजन में पटना हाई कोर्ट के जज एवं वकीलों समेत समाज के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एवं जस्टिस सहाय के पुत्र राजकुमार सहाय ने किया। पटना हाईकोर्ट के अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस प्रेमशंकर सहाय ने पिपरा, पारसविगहा, सहवालिया समेत कई चर्चित नरसंहारों में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहीं गोपालगंज कलेक्टर मर्डर केस में भी उनके द्वारा दिए गए फैसले की उस दौरान पूरे सूबे में जबरदस्त चर्चा हुई। पूर्व जज जस्टिस प्रेमशंकर सहाय का जन्म 25 नवम्बर 1924 में हुआ था। इस मौके पर उनके सुपुत्र व पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता राजकुमार सहाय के द्वारा जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल भी बांटा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता जस्टिस प्रेमशंकर सहाय को सामाजिक कार्यों में काफी अभिरुचि थी। जहां भी उन्हें महसूस होता समाज में उस कार्य को तत्परता से करने हेतु वे स्वयं ही आगे आते थे। यही वजह रही कि सेवानिवृत के बाद भी वे दर्जनों सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर सक्रियता से वहां अपनी भागीदारी बेहतर ढंग से निभाते रहे तथा जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने मानव सेवा का कार्य करते रहे। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर सहाय बहुत ही प्रियभाषी, सुशील, कुशाग्र बुद्धि और मिलनसार व्यक्ति थे। वह जहाँ भी रहे उन्होंने अपना अमिट छाप दुनिया में छोड़ दिए। वे हमेशा मानव सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय 1976 से 1986 तक पटना हाई कोर्ट के जज रहे। 1983 में जस्टिस प्रेमशंकर सहाय पर गोली चलाया गया था, जब वह कोर्ट न0-7 के पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे थे। भगवान का कृपा था कि जस्टिस प्रेमशंकर इस घटना में बाल-बाल बचे थे। यह पूरे भारत की पहली घटना थी जब किसी वर्तमान जज पर हाईकोर्ट में गोली चली हो। इस घटना के उपरांत पटना हाई कोर्ट की एवं जजों की सुरक्षा को बढ़ाया गया। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय 25 नवम्बर 1986 को पटना हाई कोर्ट के जज पद से सेवानिवृत हुए। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय के सुपुत्र एवं जाने माने अधिवक्ता राजकुमार सहाय ने कहा कि उनके पिता जी को इस बात का कभी गुरूर नहीं रहा कि वह इतने बड़े पद पर आसीन रहे। वह हमेशा समाज के लोगों की सेवा में लगे रहे। आज उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम उनके पदचिन्हों पर चलने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि जस्टिस प्रेम शंकर सहाय न केवल एक कानूनविद थे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी उनकी खासी दिलचस्पी रही थी। इसी कारण जस्टिस सहाय कई सामाजिक संस्थाओं से न केवल जुड़े रहे अपितु वहां एक दायित्व के साथ काम करने में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित की। चाहे वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र एसोसिएशन के गठन की बात हो या महात्मा गांधी के वैचारिक मुद्दों पर आधारित संस्थान सदाकत आश्रम के संचालन का या फिर कई अन्य सामाजिक संस्थान का। जहां न केवल उन्होंने सक्रिय भूमिका में एक दायित्व के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की अपितु कईयों का तो उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा गठन तक किया। 1969 में जस्टिस सहाय परिणय सूत्र में बधे थे। उनकी पत्नी श्रीमति विणा सहाय उत्तर प्रदेश के लखनऊ से थी। उनकी पत्नी इतिहास और दर्शनशास्त्र से स्नातकोत्तर (एम.ए.) थी। श्रीमति विणा सहाय बहुत ही अच्छी गायिका, चित्रकार और लखनऊ के रेडियो स्टेशन में उद्घोषक थीं। वह शाकाहारी थीं। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय को पुत्र का सौभाग्य 1971 में प्राप्त हुआ।

पटना में कैंसर के रोगियों का इलाज कैसे सुलभ हो सके, उसके लिए उन्होंने महावीर कैंसर हॉस्पिटल संस्थान जैसे बडे अस्पताल का निर्माण एवं संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाई। आम रोगियों के सस्ते इलाज के लिए महावीर आरोग्य एवं वात्सल्य संस्थान का निर्माण भी उन्होंने अपनी देख रेख में कराया और वर्षो तक महावीर मंदिर, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर वात्सल्य और कैंसर अस्पताल का अध्यक्ष बनाया गया। वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और गोवा के ऑयल चयन समिति के चेयरमैन भी रहे। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित जीवन बीमा निगम के निदेशक के पद पर एक वर्ष के लिए रहे। दो वर्ष के लिए मगध स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक के साथ-साथ बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। वहीं पटना में वह इंडस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष भी थे। जस्टिस प्रेम शंकर सहाय बिहार के विश्वविद्यालय में चांसलर रहे हैं।

शताब्दी कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के वरीय एडवोकेट वाई. वी. गिरी, एन. के. अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेड डी.बी गुप्ता, बिहार पंजाबी बिरादरी के अध्यक्ष दिलजीत खन्ना समेत सैकड़ो लोग मौजूद रहे।●

माननीय न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल की स्मृति में श्रद्धांजलि

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

मधेपुरा के मुरहो के मंडल परिवार के प्रतिभावान शख्सियत जस्टिस किशोर कुमार मंडल जिनका देहांत नई दिल्ली स्थित आईएलबीएस में 7 जुलाई 2024 को हो गया था। उन्हें 9 जुलाई 2024 को पटना के बाँस घाट पर अग्नि को सुपुर्द करके अंतिम विदाई दी गई। 10 जुलाई 2007 को वे हाईकोर्ट जज नियुक्त हुए और 7 जुलाई 2009 को उन्हें जज पद पर नियमित किया गया था।

सेवानिवृत न्यायाधीश किशोर कुमार मंडल का जन्म 22 जनवरी 1956 को श्रीमती भाग्यमणि मंडल और न्यायमूर्ति राजेश्वर प्रसाद मंडल के चौथे और सबसे छोटे बेटे के रूप में बिहार के मधेपुरा जिले में पूर्व मुरहो एस्टेट के प्रतिष्ठित मंडल परिवार में हुआ था। जस्टिस मंडल स्वर्गीय भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल के पोते थे जो 1924 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे और बाद में 1932 से 1948 में अपनी मृत्यु तक भागलपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे। जस्टिस मंडल एक महान बाबू रासबिहारी लाल मंडल के परपोते थे। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और एआईसीसी सदस्य थे और उन्होंने दिसम्बर 1910 में अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा का गठन भी किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बी.पी. मंडल, जस्टिस मंडल के दादा थे। स्वर्गीय सुरेश चंद्र यादव, पूर्व

विधायक और स्वर्गीय रमेश चंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमूर्ति मंडल के चाचा थे। मधेपुरा के प्रख्यात चिकित्सक डॉ. अरुण कुमार मंडल एवं सुधीर मंडल और शेखर मंडल दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में जस्टिस मंडल के बड़े भाई हैं। न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल ने वर्ष 1980 में पटना उच्च न्यायालय के बार में शामिल होकर अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्हें जल्द 1996 में ही कई सरकारी पैनलों में नियुक्त किया गया और उन्होंने सरकार की ओर से उन्हें दिए गए अधिकांश कार्यों में अनुकूल आदेश और निर्णय प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में उन्हें सरकारी वकील (जीपी) के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति के. के. को दिसंबर 2004 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उन्हें भारतीय रेलवे के लिए वरिष्ठ वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वर्ष 2004 में उन्हें निर्विरोध रूप से पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया। पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद 7 जुलाई 2009 को इसकी पुष्टि की गई। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति के. के. मंडल कई प्रशासनिक समितियों से जुड़े रहे। वह बिहार न्यायिक अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। वे 21 जनवरी 2018 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत हुए। राज्य सरकार ने उन्हें राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना के अध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्त किया, जिसमें वे 21 फरवरी 2018 को शामिल हुए।

न्यायमूर्ति के. के. मंडल को 20/06/2023 को बुखार हो गया था। उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल मे मर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें पटना से 1 जुलाई 2023 को एयर एम्बुलेंस द्वारा

इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज, नई दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी स्थिति में वहाँ भी सुधार नहीं हो सका और 7 जुलाई 2023 को सुबह 7.40 बजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम साँसे ली। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती मीनू मंडल, दो बेटियां-रितु मंडल और रुचि मंडल और एक बेटा हर्ष मंडल हैं। जस्टिस के. के. मंडल की छोटी सुपुत्री रुचि मंडल दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं और कानून के जाने माने जानकार हैं। जस्टिस के. के. मंडल आपराधिक और संवैधानिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार थे। जस्टिस के. के. मंडल के बड़ी सुपुत्री रितु मंडल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं। इनके छोटे सुपुत्र हर्ष मंडल हैदराबाद के एमएनसी में कार्य कर रहे हैं। जस्टिस किशोर कुमार मंडल अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए आज भी याद किए जाए जाते हैं।

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चन्द्रन, जस्टिस राजीव रॉय, जस्टिस आशुतोष कुमार, कई सेवानिवृत जज, पूर्व मंत्री नरेन्द्र कुमार यादव, संजय सिंह प्रवक्ता (जदयू) आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। जस्टिस के. के. मंडल के परिवार से उनका भतीजा डॉ० मनीष मंडल IGIMS पटना अधीक्षक शेखर मंडल, डॉ. सूरज मंडल, आनंद मंडल, निखिल मंडल उनके बहनोई डॉ विनोद यादव, पूर्व विधायक, साले श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह (जमुई जिला जज) आदि भी उपस्थित थे।●

पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रॉय का ऐतिहासिक सफर

● **श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है। माननीय न्यायमूर्ति राजीव रॉय पटना हाईकोर्ट में 29 मार्च 2022 को शपथ लिए। न्यायमूर्ति राजीव रॉय संवैधानिक, प्रशासनिक और आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं। यह पटना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के चर्चित वकील रहे हैं। न्यायमूर्ति राजीव रॉय के पिता स्व. मोतीलाल रॉय पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता रहे हैं। यह श्रीमती राजकुमारी रॉय के सुपुत्र हैं। इनके दादाजी बी.बी. यादव पटना के प्रसिद्ध लकड़ी व्यापारी रहे हैं। जस्टिस राजीव रॉय के दादी जी स्व. चमेली देवी थी। इन्होंने अपना स्कूली शिक्षा राम मोहन रॉय सेमिनरी, पटना से पूरा किया। जस्टिस राजीव रॉय जंतु शास्त्र से स्नातक Science College Patna University से किए। इन्होंने जंतु शास्त्र में स्नातकोत्तर (M.Sc. Zoology) भी पटना विश्वविद्यालय से पूरा किए। जस्टिस राजीव रॉय कानून में स्नातक1989 में किए।

जस्टिस राजीव रॉय पटना हाईकोर्ट में 1990 में स्व. वरीय अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में वकालत की शुरुआत की। वरीय अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिन्हा के निधन के उपरांत जस्टिस रॉय के.के. मंडल के कार्यालय से जुड़े। किशोर कुमार मंडल 2007 में के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। जस्टिस राजीव रॉय पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर 2009 से 2011 तक रहे। जस्टिस राजीव रॉय बिहार सरकार के वकील के रूप में 2016 से 2021 तक रहे। इन्होंने इस पद से 2021 में इस्तीफा दे दिया। जस्टिस राजीव रॉय की पत्नी श्रीमती मधु रॉय है। जस्टिस राजीव रॉय की सुपुत्री दीप्ति रॉय हैं, जो एक इंजीनियर हैं।

जस्टिस राजीव रॉय का एक विडियो चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कोर्ट रूम में पान चबाने पर वकील को टोका एवं जुर्माना भी लगाया था। जस्टिस राजीव रॉय अपने फैसले से अभी हाल ही में चर्चा में रहें, जिसमें उन्होंने काफी सख्त टिपणी बिहार सरकार में बीडीओ (प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों) पर किए। बीडीओ की मिलीभगत स्थानीय नेताओं के साथ बना रहता है। जस्टिस राजीव रॉय ने राज्य सरकार को काफी सख्त दिशा-निर्देश अपने फैसलों में दिए हैं। उन्होंने सभी बीडीओ को न्यायसंगत कार्य करने का आदेश दिए हैं। बीडीओ द्वारा किसी स्थानीय नेताओं के भी प्रभाव में आकर कार्य करने पर बीडीओ पर सख्त कार्रवाई करने का चेतावनी दिया गया है।●

बिक्रम ट्रॉमा सेंटर चालू होने की जगी आस!

● विकाश कुमार/ संतोष कुमार

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नही होती यह कथन अंजनी सिंह पर सही बैठता है। बिक्रम ट्रॉमा सेंटर को एक एकड़ जमीन मिलने का आदेश निर्गत हुआ है। इस ट्रामा सेंटर के लिए अंजनी सिंह और संघर्ष समिति ने लंबी लड़ाई लड़ी है। बिक्रम में वर्षो से चल रही ट्रॉमा सेंटर की मांग पर राज्य सरकार ने अपनी स्वकृति की मुहर लगा दी है। जल संसाधन विभाग ने प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर के लिए असपुरा पीएचसी के बगल में अपनी एक एकड़ जमीन ट्रॉमा सेंटर निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण करने के लिए आदेश निर्गत किया है। ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन मिलने की आदेश निर्गत होने की खबर से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। दो दशक पूर्व बिक्रम ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, लेकिन राजनीतिक दांव पेंच के कारण आज तक चालू नहीं हो सका। अंजनी सिंह तथा क्षेत्रीय लोगों द्वारा चालू कराने को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। इस ट्रॉमा सेंटर को चालू कराने के लिए अंजनी सिंह ने तथा संघर्ष समिति ने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। अंजनी सिंह कि अध्यक्षता में जन संवाद यात्रा का आयोजन भी किया गया था। जिसमें हजारो कि संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। लोगों का मानना था कि जन संवाद यात्रा सफल हुआ था, उसके बाद अंजनी सिंह ने गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाये

थे। इस ट्रॉमा सेंटर को चालू कराने के लिए लोगों ने अनिश्चित कालीन धरणा पर भी बैठे थे। और अंतत: एक एकड़ भूमि का आवंटन हो गया। इस तरह के लगातार अंदोलन होने से यहॉ के स्थानीय नेता में अंजनी सिंह का खौफ पैदा हो गया। बिक्रम विधानसभा का उभरता हुआ चेहरा अंजनी सिंह जनता के दिलों पर अमिठ छाप छोड़ी है। ये जनता के नाम से सोते है और जनता के नाम से हि जगते है। जनता के खुसहाली के लिए हर संभव कोशिश करते है। अंजनी सिंह अपने क्षेत्र के जनता के लिए कई आवाज उठाये। उस क्षेत्र के जनता का कहना है कि अंजनी सिंह ने कनपा से बेरर पथ के पक्की के लिए आवाज उठाये थे। उसके बाद ये पथ बना है। वही बेरर से करहरी के लिए भी अंजनी सिंह ने ही जनता का आवाज बने। उसके बाद यह पथ पर काम लगा है। अभी अंजनी सिंह का मांग है कि धना परेवा नहर में पानी नही छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही अंजनी सिंह चाहते है कि बिक्रम का डाकबंगला बहुत ही बुरा स्थिति में है जिसे बनना चाहीए साथ ही साथ बिक्रम का त्रिभुवन पुस्तकालय भी बुरा स्थिति में है जिसे बनना जरूरी है। ये जात-पात के राजनीति नही करते है जिसके कारण इनका अगड़ी जाती के साथ-साथ पीछड़ी जाती में भी लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है। उनका सबसे ज्यादा फोकस आपसी समन्वय बनाने पर रहता है। उनका हमेशा प्रयत्न रहता है कि किस प्रकार गरीबों को दलदल से निकाला जाये। ताकी समाज को सही दिशा में ले जाया जाये इसके लिए हमेंशा प्रयासरत रहते हैं। अंजनी सिंह और संघर्ष समिति के प्रयास के बाद बिक्रम ट्रॉमा सेंटर के निर्माणा की आस जनता में जगी है। बिक्रम ट्रॉमा सेंटर के बन जाने के बाद मरीजो को जान बचाना आसान हो जायेगा। बिक्रम ट्रॉमा सेंटर के चालू हो जाने के बाद गंभीर दुघटनाओं और आपातकालीन स्थिति में इलाज की सुविध ा हो जायेगा। दुर्घटनाओं या गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों में त्वरित और प्रभावी इलाज मिलने की संभावना बढ़ेगी। ट्रॉमा सेंटर को चालू हो जाने से स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन जायेगा, जिससे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवता में सुधार होगा। साथ ही साथ यहॉ विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की तैनाती होगी, जो खासकर गंभीर मामलों का इलाज करने में सक्षम होंगे। इससे न केवल लोंगों को बेहतर इलाज मिलेगा, बलिक यह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करेगा। अंजनी सिंह के संघर्ष का यह बहुत बड़ा उपलब्धी है, जिसे जनता हमेंशा याद करेंगी। अंजनी सिंह बिक्रम विधानसभा में उभरता हुआ लोकप्रिय चेहरा बन चुके है। इनके कार्य करने की शैली एवं प्रयास ऐसे ही चलते रहे तो अंजनी सिंह भी एक मजबूत चेहरे के रूप में बिक्रम विधानसभा को नयी पहचान दे सकते है। अंजनी सिंह बिक्रम क्षेत्र के लिए कुछ विशेष करना चाहते है, जिससे उनका एक अलग पहचान बने और समाज उन्हे उस कार्य के लिए हमेशा याद करे। वे कोई ऐसी विशिष्टता हासिल करना चाहते है, जो उन्हे उस भीड़ से अलग करे। वे अपने क्षेत्र के जनता के बीच रहते है तथा उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को वे ब खुबी समझते है तथा उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिष करते है। जिसका काम करना ही लक्ष्य है तो भला उसका कोई क्या

बिगाड़ लेगा। अंजनी सिंह चाहते है कि हर व्यक्ति का मान-सम्मान हो तथा हर व्यक्ति तक सरकार का योजनाओं का प्रकाश हर घर तक पहुँचे यही उनका उददेश्य है। जनता का कहना है कि अंजनी सिंह का पूरा प्रयास रहता है कि जो हमारे पास जिस उम्मीद से आते है, उनके उसी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते है, ताकि वे नाउम्मीद हो कर न जाये। हर बुनियादी सुविधाएँ उचित हकदार तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करते है। किसी की बेटी की शादी हो या बिमारी या कोई अन्य परेशानियों में अंजनी सिंह निजि रूप से हर संभव मदद करने को प्रत्यनशील दिखते है।

मिलनसार एवं मृदुभाषी होने के कारण अंजनी सिंह बहुत कम दिनो में जनता के बीच एक नेता के रूप में पहचान बनाये है। ऐसा प्रतित होता है कि अंजनी सिंह को जनता भावि विधायक के रूप में देख रही हैं। बिक्रम विधानसभा के जनता का मिजाज अपने पक्ष में करने में कामयाब भी होते दिख रहे है। अंजनी सिंह अपनी कर्मठता, दक्षता, योगता एवं अनुभव के दम पर जनता में खुब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अंजनी सिंह युवा नेता है तथा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी है। युवाओं के बारे में उनका मान्ना है कि युवा देश के भविष्य है, इन्हें अपनी कार्यक्षमता एवं शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और युवाओं के लिए ये हर संम्भव प्रयास करते है। जो भी युवा भटक जाते है उन्हें वे समझा कर उसे सही रास्ते पर लाने कि कोशिश करते है। अंजनी सिंह का कहना है कि गरीब जनता जिसे मुलभुत सुविधा कि जरूरत है उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करेंगें। गरीब जनता के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा योजनाओं में पूरी तरह लुट मची है। यहाँ का जनता भ्रष्ट्राचार से त्रस्त है, भ्रष्टाचार को हर संभव दूर करने की कोशिश करेंगें। अंजनी सिंह का कहना है कि मैं इस क्षेत्र का चैमुखि विकास करना ही मेरा लक्ष्य हैं। और समाज का सच्चा सेवक बन कर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उनका कहना है कि मै कई वर्षो से जनता का सेवा कर रहा हूँ तो जिस ढ़ंग से जनता का हुजुम रहता है उससे लगता है कि मै जो ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, उसी का परीणाम है। मै हमेशा जनता के बिच में रहा हूँ तथा उनके सुख-दु:ख में हमेशा खड़ा रहता हूँ तो उसी का नतीजा है कि समाज के हर काम में जनता मेरा साथ देती है। जनता का प्यार ही मेरी मजदूरी है। जनता की सेवा ही मेरा प्राथमिकता है। जनता से मुझे कहना यही है कि सेवा करने वाले को ही अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का मैका देना चाहीए। तथा वे अपने बीच रहने वाले व्यक्ति को ही नेता चुने। ताकी वे हमेशा जनता के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने हर कर्तव्य का निर्वहन करें। यहाँ बदलाव की जरूरत है। अंजनी सिंह का कहना है कि आपसी बिवाद भी इस क्षेत्र का मुलभुत समस्या रहा है। कई लोगो को केश मुक्दमा में तथा सुलह समझोता कराने में भी मेरा अहम रौल रहा है। ताकी आपसी बिवाद से लोग दूर रहे और हँसी-खुशी का माहौल बना रहे। ऐसे कई सम्स्याओ का समाधान करने में अंजनी सिंह का पुरा भागिदारी रहा है। परन्तु इस क्षेत्र में कई ऐसे छोटे-बड़े समस्या है जिसे इन्हे कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता हाथ लगेगा। इस क्षेत्र के जनता आज भी बदहाली की उस दौड़ से गुजर रही है जो आज के 15 साल पहले था। इस क्षेत्र में विकास की किरण आज भी पूरी तरह नही पहुँच पाई है अर्थात इस क्षेत्र का विकास कोषो दूर है। वही इस क्षेत्र के मुलभुत समस्या रही है बिजली,सड़क,पानी, किसानो का समस्या और स्वास्थ्य। अब बात स्वास्थ्य कि करे तो इस क्षेत्र के कई ऐसे स्वास्थ्य उप केन्द्र है। जो सुचारू रूप से चले तो इस क्षेत्र के जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकता है। बिक्रम का टॉमा सेंटर से जनता में एक आशा कि किरण जगी है। ऐसे में इन्हे इस क्षेत्र के मुलभुत सुविधाओं को धरातल पर लाने में कठीन मेहनत करनी होगी तथा आशा है कि अंजनी सिंह जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे।●

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भाजपा को बदनाम न करें

ठेकेदारी और ईमानदारी साथ-साथ नहीं चल सकती

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कहा है कि ठेकेदारी और ईमानदारी साथ-साथ नहीं चल सकती है। एक इस तरफ ठेकेदारी करवाना दूसरी तरफ जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना ऐसा नहीं हो सकता है।

उपमुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सड़कों और पुलों के रखरखाव संबंधित लोक शिकायत निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के अनुसार इस नई व्यवस्था के बाद अब राज्य के आम लोग भी अपने- अपने इलाकों में खराब सड़क, पुल के बारे में ऑनलाइन शिकायत पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब आम लोग मोबाइल नंबर 947 000 1266 पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नई व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है है। अब जनता से जुड़कर अभियंता और ठेकेदार के गठजोड़ को तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत प्राप्त होते ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा प्रतिवेदन त्रुटि को फोटो सहित संबंधित संवेदक को सुधार हेतु भेजा जाएगा ,इसके बाद संवेदक द्वारा निराकरण किया जाएगा और शिकायत को फोटोग्राफ भेज कर विभाग को अवगत कराया जाएगा। अभियंता द्वारा स्थल के नीरिक्षण के बाद मानक के अनुसार कार्य किए जाने पर स्वीकार किया जाएगा अन्यथा संवेदक को दोबारा मरमती हेतु निर्देश दिया जाएगा। मानक के अनुसार नहीं बनाए जाने पर कार्रवाई के लिए चर्चा तक नहीं की गई। कितना दुर्भाग्य की बात है की अंग्रेज की जाने के बाद भी उसके द्वारा बनाया गया पुल आज भी सीना तानकर खड़ी है, दूसरी और आजादी के बाद निर्माणाधीन के समय ही पूल धराशाई हो रहा है बावजूद एक भी इंजीनियर जेल नहीं गया होगा। नियमत:कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए पुलिस को देनी होगी परन्तु पुलिस होना देखो अभियंता के सुरक्षा अधिकारी को दी जाती है। चीन में इंजीनियर के लापरवाही से एक पूल टूट जाने पर उस इंजीनियर को एक बोरा में कसकर उसी नदी में डाल दिया गया था। इसी तरह भारत में भी कानून बनाकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।●